दैनिक जागरण

उचित क्रियान्वयन के बिना अच्छी से अच्छी योजना भी व्यर्थ है

बदलता जम्मू-कश्मीर

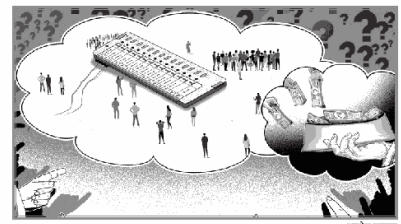

प्रधानमंत्री ने ऊधमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही रेखांकित किया कि अब जम्मू-कश्मीर में एक ओर जहां सड़क, पुल, अस्पताल, रेल नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा संस्थान बन रहे हैं, वहीं हाल के इतिहास में पहली बार है, जब आतंकवाद, पत्थरबाजी, अलगाववाद, सीमा पार से गोलीबारी जैसे विषय चुनावी मुद्दे नहीं हैं। निःसंदेह यह सब जम्मू-कश्मीर में एक बड़े और बुनियादी बदलाव का सूचक है। जम्मू-कश्मीर में बदलाव के कुछ और स्पष्ट संकेत भी हैं, जैसे रिकार्ड संख्या में पर्यटकों का जाना और हाल में गृहमंत्री अमित शाह का यह कहना कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा हटाने पर विचार करेगी। उनके अनुसार जम्मू-कश्मीर से सेना को हटाकर कानून एवं व्यवस्था को राज्य पुलिस के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से घाटी में बदलाव का एक प्रमाण यह भी है कि वहां सिनेमाघर खुलने के साथ खेल गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं और पूंजी निवेश में वृद्धि भी हो रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वहां कुछ अंतरराष्ट्रीय आयोजन भी हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने ऊधमपुर में अनुच्छेद-370 हटाए जाने से जम्मू-कश्मीर के लोगों और विशेष रूप अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय को मिलने वाले लाभ गिनाकर एक तरह से यही बताया कि यह अनुच्छेद कितना पक्षपाती, विभाजनकारी और लोगों के अधिकारों को कुचलने वाला था। शायद इसी कारण उन्होंने न केवल यह कहा कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद-370 की दीवार गिराने के साथ उसका मलबा भी जमीन में गाड़ दिया है, बल्कि यह चुनौती भी दी कि विपक्ष में यह साहस नहीं कि इस अनुच्छेद की वापसी की बात कर सके। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की कि वह दिन दूर नहीं, जब जम्मू-कश्मीर में न केवल विधानसभा चुनाव होंगे, बल्कि वह पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर में इसी वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री के कथन से यह तो स्पष्ट नहीं कि विधानसभा चुनाव होने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि ऐसा किया जाना मोदी सरकार के एजेंडे में है। जैसे ही यह एजेंडा पूरा होगा, पस्त पड़े अलगाववादी तो कश्मीर के लोगों को बरगलाने का अवसर गंवा ही देंगे, पाकिस्तान भी कश्मीर पर और निहत्था हो जाएगा। इसके बाद भी उचित यही होगा कि विधानसभा चुनाव के उपरांत ही यह आकलन किया जाए कि राज्य के दर्जे की बहाली कब की जाए? यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि एक तो आतंकी छिटपुट हमले करते रहते हैं और दूसरे, कश्मीरी हिंदू अभी अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। जितना जरूरी जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना और राज्य के दर्जे की बहाली करना है, उतना ही यह भी कि कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौटने के साथ वहां निर्भय होकर रह सकें।

यात्रा की तैयारी

उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा आरंभ होने वाली है। देश में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच शुरू हो रही यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड सरकार भी तैयारियों में जुटी हुई है। यद्यपि, अभी प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव में व्यस्त रहने के कारण यात्रा की तैयारियां गति नहीं पकड़ पा रही हैं। प्रदेश में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इससे मतदान के बाद विभागों को तैयारियों को कुछ समय जरूर मिल जाएगा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा। चार धाम यात्रा में पुलिस, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पुलिस चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है। ऐसे में मतदान के बाद उसकी तैयारियां गति पकड़ेंगी। पर्यटन विभाग ने चारों धाम की यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया है। इसी समय हेली बुकिंग भी शुरू की जाएगी। यात्रियों का यात्रा पूर्व परीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का कार्य चल रहा है और बदरीनाथ व केदारनाथ में निर्मित चिकित्सालयों के लिए उपकरण खरीद के टेंडर हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग मार्गों को दुरुस्त व सुरक्षित करने का कार्य कर रहा है। सुरक्षित चार धाम यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवहन विभाग की है, जिसने ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य आनलाइन शुरू कर दिया है। 19 अप्रैल को मतदान के बाद सभी विभागों के पास यात्रा की तैयारियों के लिए 20 दिन का समय होगा। इस अवधि में पूरी व्यवस्था को धरातल पर उतारना आसान नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि सरकार सभी विभागों को लोकतंत्र के महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही प्रदेश की आर्थिकी और पहचान से जुड़ी चार धाम यात्रा को व्यवस्थित व सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए समानांतर रूप से तैयारियों के लिए निर्देशित करे।

चुनाव सुधारों से इन्कार

शिवकांत शर्मा

यह देखना दयनीय है कि चुनाव सुधारों पर आगे बढ़ने की जगह, पीछे हटने की बातें होने लगी हैं

अवधेश राजपूत

अमेरिका के विनोदप्रिय लेखक और अभिनेता राडनी डेंजरफील्ड ने एक समय कहा था-20 वर्ष की आयु में व्यक्ति जुझारू और आशावान होता है। वह दुनिया बदलना चाहता है। 70 का होने पर वह बदलना तो चाहता है, पर जान जाता है कि बदल नहीं सकता।' भारत पर यह कथन पूरी तरह लागू होता है। भारतीय गणतंत्र की उम्र जैसे-जैसे बढ़ रही है, सुधार करना कठिन होता जा रहा है। चुनाव सुधारों पर आगे बढ़ने की जगह पीछे हटने की बातें होने लगी हैं। बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार की बात तो छोड़ दीजिए, बढ़ती चुनावी हिंसा, धांधली और चुनावों की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए जिस ईवीएम का विकास किया गया, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मशीनों से मतपत्रीय मतदान की बहुत सी समस्याएं हल हुई थीं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय से मतपत्रों पर लौटने की अपील की जा रही है।

चुनावों को लेकर सबसे बड़ी समस्या प्रचार खर्च और उसके लिए आवश्यक चंदे की है, जिसके समाधान के लिए आजादी के पहले से ही मंथन होता आ रहा है। गांधीजी ने कभी कहा था कि भारत जैसे गरीब देश में यदि उम्मीदवार अपने चुनावों में 60 हजार से एक लाख रुपया खर्च करेंगे तो कैसा घोर अन्याय होगा? गांधीजी की चिंता उनके साथ चली गई। उनके बाद सार्वजनिक जीवन में फैलते भ्रष्टाचार से चिंतित होकर लाल बहादुर शास्त्री ने गांधीवादी के. संथानम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया कि सभी दलों को हर स्रोत से मिले चंदे और उसके खर्च का पूरा हिसाब रखना और उसका ब्योरा आडिट के साथ हर साल देना चाहिए। चुनावी बांडों पर विवाद की पृष्ठभूमि में संथानम समिति की वह सिफारिश और भी प्रासंगिक हो जाती है।

चुनाव प्रचार में होने वाला औसत खर्च विधानसभा के लिए 20 करोड़ और संसदीय चुनाव के लिए 50 करोड़ तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख और लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख की अधिकतम सीमा तय की है, जो हास्यास्पद रूप से कम है। इससे चुनाव आयोग भी अवगत है, पर वह प्रचार खर्च की सीमा दलों की सलाह से ही तय करता है। दल चाहें तो इसे बढ़वा कर वास्तविकता के करीब ला सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। वे न तो प्रचार खर्च का पूरा हिसाब देना चाहते हैं और न अपने चंदे के सभी स्रोतों का। प्रचार का ज्यादातर खर्च नकद होता है, जो आम तौर पर काला पैसा होता है। चुनाव प्रेक्षकों का मानना है कि भारत के आम चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों से भी अधिक खर्चीले हो चुके हैं, जिनका खर्च एक लाख करोड़ रुपये से भी ऊपर चला गया है। भारत में आम चुनाव विज्ञापनों, जलसे-जुलूसों और पोस्टरबाजी की होड़ के अलावा वोट खरीदने के लिए बांटे जाने वाले उपहारों और नकदी की वजह से खर्चीले हो रहे हैं। लोग पैसा लेकर वोट भले अपनी मर्जी से देते हों, पर वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें मिलने वाला पैसा पार्टियों को ठेकों व नियमों में मिलने वाली रियायतों की आशा से दिया जाता है। साफ है कि वोटों के लिए मिलने वाला मामूली पैसा मतदाता को बहुत महंगा पड़ता है। वह सार्वजनिक भ्रष्टाचार की जड़ है।

इंदिरा गांधी सरकार राजनीतिक दलों और नेताओं को विदेशी जासूसी संस्थाओं और दूतावासों से मिलने वाले चंदे को लेकर इतनी चिंतित हुई थी कि केंद्रीय गुप्तचर विभाग से जांच करा डाली। जांच की रपट दबा दी गई, क्योंकि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सोवियत संघ से चंदा लिया था। उसके बाद पिछली सदी के नौवें दशक में उनकी ही सरकार पर अनाज, तेल और रक्षा सौदों के जरिये चंदा उगाहने के आरोप लगे। इसी पृष्ठभूमि में लोकतांत्रिक सुधार संघ नामक संस्था ने चुनावी बांड का सुझाव दिया, जिस पर बरसों के विचार के बाद 2017 में कानून बना। लोकतांत्रिक सुधार संघ ने कानून का मसौदा देखते ही उसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि उसे मसौदे के इन चार प्रविधानों पर आपत्ति थी कि बांड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे गए। दान की सीमा हटा दी गई। कंपनियां ट्रस्ट बनाकर बांड खरीद सकती थीं और बांड पर नाम न होने की वजह से उसका विनिमय भी हो सकता था। इन्हीं चार दोषों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बांड वाले कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया। आखिर इस फैसले के बाद शोर मचाने वाले विपक्ष और मीडिया ने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई, जब उक्त कानून संसद में पेश किया गया था?

लगभग छह साल चली चुनावी बांड योजना का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गोपनीयता और सीमा रहित दान जैसे प्रविधान होते हुए भी चुनावी बांडों से मिला लगभग 16.5 हजार करोड़ रुपये का चंदा आम चुनावों में खर्च होने वाले एक लाख करोड़ का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि चुनावी बांडों के बावजूद चंदे की बड़ी रकम नकद या दूसरे माध्यमों से आती रही। देने वाले कारपोरेट, विदेशी, अपराधी कोई भी हो सकते हैं। पार्टियों को केवल 20 हजार से अधिक चंदा देने वालों का रिकार्ड रखना और हर साल टैक्स रिटर्न भरना होता है। चंदा देने वाले को तो टैक्स छूट मिलती है, पर पार्टियों को चंदे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। पार्टियां हर साल टैक्स रिटर्न भरने में भी आनाकानी करती हैं, जिसे लेकर विवाद होते हैं।

भारत में राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना आसान नहीं है। कारपोरेट चंदा बंद कर दलों को सरकारी पैसे से चलाने की बातें व्यावहारिक नहीं, क्योंकि राजनीतिक कड़वाहट और अविश्वास को देखते हुए सरकारी पैसे के बंटवारे पर विवाद होगा। सरकारी अनुदान मिलने पर भी दल यदि अपने प्रचार में काला पैसा खपाएंगे तो उसे कैसे रोकेंगे? दलों को उनके जनसमर्थन के आधार पर कुछ सरकारी अनुदान देने और बदले में नकद लेनदेन पर पाबंदी लगाने और पारदर्शिता के नियम सख्ती से लागू करने से कुछ फर्क पड़ सकता है। अधिकतर पश्चिमी लोकतंत्रों में इसी तरह की मिश्रित व्यवस्था है। कोई राजनीतिक सुधार जनता की सहमति और सहयोग के बिना नहीं हो सकता। जार्ज बर्नार्ड शा ने ठीक ही कहा है-लोकतंत्र वह साधन है, जो सुनिश्चित करता है कि हमें उससे बेहतर शासक न मिलें, जिसके हम लायक हैं।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

बदलते भारत से अनभिज्ञ कांग्रेस

अवधेश कुमार

इस समय कांग्रेस नेतृत्व यह समझने को तैयार ही नहीं दिखता कि उसके नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं?

चुनाव के दौरान नेताओं का पार्टी छोड़ना और दूसरी पार्टी में जाना भारतीय राजनीति में बहुत ही सामान्य घटना मानी जाती है। भाजपा से भी कुछ लोग दूसरी पार्टियों में गए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जितनी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वह असाधारण है। इधर तो लगभग हर दिन कोई न कोई नेता कांग्रेस छोड़ रहा है। 1977 में कांग्रेस की सबसे बुरी स्थिति के दौरान भी इतनी संख्या में लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी थी। कई राज्यों में तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पार्टी ही भाजपा में जाने को तैयार हो। गुजरात में ऐसा कोई जिला नहीं, जहां कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग भाजपा में न जा चुके हों। यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। इस पर कांग्रेस नेतृत्व जो भी प्रतिक्रिया दे, 2024 का लोकसभा चुनाव पार्टी के भविष्य की दृष्टि से सबसे बड़े संकट का समय बन गया है। हाल में पार्टी के तीन नेताओं संजय निरुपम, गौरव वल्लभ और रोहन गुप्ता ने पार्टी छोड़ते समय जो कुछ कहा वह कांग्रेस के अंदर विचार, व्यक्तित्व और व्यवहार, तीनों प्रकार के संकटों को स्पष्ट करने वाला है। तीनों ने जो कहा, उसका सार यही है कि कांग्रेस पार्टी अब सनातन विरोधी हो गई है। देश में जो संपत्ति सृजन कर रहे, उनके खिलाफ बोल रही है। नेहरू जी के सेक्युलरवाद को देश बहुत पीछे छोड़ चुका है, जबकि वर्तमान कांग्रेस वामपंथियों के प्रभाव में उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गांधीजी की धारा सर्वपंथ समभाव की थी, जबकि नेहरू का सेक्युलरिज्म मूल रूप में एंटी रिलीजन यानी मत-पंथ और यहां तक कि धर्म विरोधी भी था। यह वामपंथियों की धारा थी। कांग्रेस इस समय वामपंथियों के प्रभाव में है। इसी कारण सनातन धर्म के विरुद्ध वक्तव्यों का कांग्रेस प्रखर विरोध नहीं करती। अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना इसी धर्म विरोधी सेक्युलरवाद का अंग था। संभव है कांग्रेस के लाखों अन्य कार्यकर्ता भी ऐसा ही महसूस कर रहे हों।

कांग्रेस के अंदर विद्रोह पहले से पनप रहा था, लेकिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के समय से यह ज्यादा तीव्र हुआ है। कांग्रेस द्वारा निमंत्रण पत्र का उत्तर देने के साथ ही गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने अपनी आपत्ति जता दी थी। उन्होंने कहा था, समूचा देश प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव मना रहा है और कांग्रेस उसका बहिष्कार कर रही है। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर जगह-जगह से ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आने लगीं और कांग्रेस छोड़ने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई। ऐसे माहौल को देखते हुए कांग्रेस ने बयान जारी किया कि पार्टी ने किसी को अयोध्या जाने से रोका नहीं है और जो चाहे, वह जा सकता है। इससे भी विरोध थमा नहीं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नेताओं ने अयोध्या की यात्रा की और रामलला के दर्शन किए। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जमीनी वास्तविकता से कितना कटा है।

भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते रोहन गुप्ता। प्रेट्र

तमिलनाडु में जब द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू, मलेरिया कहते हुए इसके पूर्ण उन्मूलन की बात की, तब भी कांग्रेस ने विरोध में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बिहार में राजद के एक मंत्री ने भी हिंदू धर्म, रामचरितमानस के विरुद्ध लगातार बयान दिए और कांग्रेस चुप रही। लगता है कि 2014 और 2019 में पराजय झेलने के बावजूद कांग्रेस समझ नहीं पाई है कि भारत का मानस बदल चुका है। आज सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर हीनता का भाव पैदा करने का दौर पीछे छूट चुका है। आम लोग अब स्वयं को गर्व से हिंदू कहने, अपने धर्मस्थलों की रक्षा करने, उसके विकास के लिए उठकर खड़े होने तथा अपने धर्म पर लगने वाले आक्षेप का जवाब देने के लिए सामने आने लगे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश में यही माहौल है। भारत के नए सिरे से करवट लेने की गति ज्यादा सशक्त हुई है। इसके परिणाम भी दिखाई पड़ते हैं। एक समय राम मंदिर का खुलकर विरोध करने वाली पार्टियां भी शांत हैं या समर्थन में बयान दे रही हैं।

देश के मानस को न समझ पाने के कारण ही भारत से कम्युनिस्टों का केरल को छोड़कर लगभग अंत हो गया है। पिछले कुछ समय से राजनीति में हारे हुए, जनता द्वारा ठुकराए गए और समाज-राजनीति की मुख्यधारा का अंग न रहे समाजवादी और वामपंथी इस समय कांग्रेस नेतृत्व के नीति निर्धारक बन गए हैं। वे ही गांधी परिवार और विशेषकर राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं। इसी कारण इन दिनों कांग्रेस का वक्तव्य और राजनीतिक व्यवहार भाजपा विरोध के नाम पर उस अतिवाद तक चला जा रहा है, जो स्वयं पार्टी के अंदर सामूहिक सोच के विरुद्ध और भविष्य को मटियामेट करने वाला साबित हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व के अंदर यह विचार घर कर चुका है कि भाजपा को हराना सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसलिए उसे अपने हितों की बलि भी चढ़ानी पड़े तो हर्ज नहीं। कांग्रेस में एक बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं में यह भावना घर कर रही है कि हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रभाव के आधार पर बदले हुए भारत को न समझ पाने के कारण पार्टी का चुनावी और राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। उन्हें यह भी लग रहा है कि भारत की मुख्यधारा इस समय राष्ट्रवाद, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है और राजनीति में भाजपा ही उसे अभिव्यक्त कर रही है। जो पार्टी इसके विरुद्ध है, उसका केवल वर्तमान चुनाव ही नहीं, आगे भी भविष्य अंधकारमय दिखता है। नेताओं के निरंतर होते मोहभंग से भी इस रुझान की पुष्टि हो रही है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्कर्म

प्रायः देखा जाता है कि सत्कर्म करने के पीछे कुछ बेहतर प्राप्ति की आस रहती है। जैसे उन्नति, मोक्ष या अगला जन्म बेहतर करने की इच्छा। यदि अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि जितने भी दान-पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य होता है, भले ही वह स्पष्ट रूप से दिखाई न देता हो। कुछ व्यक्ति तो अपने पास पड़ी व्यर्थ की अनुपयोगी वस्तुओं को गरीबों में बांटकर स्वयं को पुण्यात्मा समझते हैं। पुण्यात्मा वह है जिसके मन, व्यवहार और वाणी सबका प्रक्षालन हो चुका हो।

मोटे तौर पर देखा जाए तो चोरी, हत्या, गबन, धोखा जैसे वीभत्स कर्मों को अशुभ कर्मों की श्रेणी में रखा जाता है। जो व्यक्ति इन सबमें लिप्त नहीं है, आवश्यक नहीं कि उसके कर्मों को शुभ कर्मों की श्रेणी में रखा जाए। यदि आप अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करते, आप वाणी से दूसरों को मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं, आप पुण्य के लोभ से दान करने में प्रवृत्त होते हैं, आप अहंकार के मद में किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो इन जैसे सभी कर्म अशुभ कर्म हैं।

स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, 'उसी कार्य को नीतिसंगत या सत्कर्म कहा जा सकता है, जो हमें जड़ के बंधन से मुक्त करता है, इसके विपरीत जो कुछ भी है वह असत्कर्म है।' वस्तुतः, ईश्वर मन की शुद्धता परखता है। शरीर से किए गए स्पष्ट अपराधों के लिए दंड का प्रविधान है, परंतु मन में खोट रखकर ऊपर से किए गए दान, पुण्य भी मुक्ति में सहायक नहीं हैं। उलटे वे जड़ के साथ हमारे बंधनों को गहरा करते हैं। हालांकि क्षमता रहते हुए भी दान न करने से पुण्य की इच्छा से दान करना बेहतर है। आत्मा की शुद्धता के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है। कई जन्मों के बाद संतत्व की प्राप्ति होती है। जैसे विद्यार्थी कई कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद विषयगत ज्ञान का अधिकारी बनता है, वैसे ही मोक्ष के अधिकारी होने के लिए कई जन्मों तक परीक्षाएं देनी होती हैं।

द्विंकल तोमर सिंह

इतिहास का कलंकित अध्याय

सुधीर कुमार

जलियांवाला बाग नरसंहार

जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने

जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। यह घटना भले ही 13 अप्रैल, 1919 को घटित हुई, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के दौर से जुड़ी है। प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान लगभग 12 लाख भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भर्ती किया गया था। विश्वयुद्ध के उपरांत भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की उम्मीद की थी, लेकिन रौलेट एक्ट के रूप में एक दमनकारी कानून तोहफे में दिया गया। सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता वाली 'राजद्रोह आयोग' की सिफारिश पर युद्धोपरांत क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए 21 मार्च, 1919 को रौलेट एक्ट लागू कर दिया गया था, जो युद्धकाल में प्रचलित 'भारत रक्षा कानून' का ही विस्तार था। इसके तहत राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए दो वर्षों के लिए कैद या नजरबंद किया जा सकता था।

गांधीजी के आह्वान पर रौलेट एक्ट के विरोध में छह अप्रैल, 1919 को देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई थी। इस बीच 10 अप्रैल को पंजाब कांग्रेस के दो स्थानीय नेताओं- डा. सत्यपाल और डा. सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन उक्त दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हुई थी। उस समय शहर में धारा-144 लागू था, जिसके तहत सभा करने, जुलूस निकालने आदि को गैर-कानूनी घोषित किया गया था, लेकिन आम लोगों को इसकी खबर नहीं थी। जलियांवाला बाग चारों ओर से मकानों से घिरा है, जिसमें बाहर निकलने का एक ही संकरा रास्ता है। इस मैदान में 15 से 25 हजार तक लोग जमा हुए थे। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। उसने अमृतसर के कमांडर जनरल डायर ने अपनी सेना को उस निहत्थी भीड़ पर बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस दौरान लगभग 1600 चक्र गोलियां चलाई गईं। गोलीबारी और भगदड़ के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए। इस घटना ने देश के स्वाधीनता संग्राम की दशा और दिशा को बदल दिया था।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जलियांवाला नरसंहार की 100वीं बरसी से पहले (2019) इस नरसंहार के लिए ब्रिटिश संसद में 'खेद' व्यक्त करते हुए कहा था कि 'जो कुछ हुआ और जो पीड़ा हुई, उस पर हमें गहरा अफसोस है।'

हालांकि इस नरसंहार को याद करना आज भी बहुत पीड़ादायक महसूस होता है। यह भी सच है कि इस नरसंहार के दोषियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। **(लेखक बीएचयू में सीनियर रिसर्च फेलो हैं)**

मेलबाक्स

एक साथ चुनाव पर समग्रता में हो विचार

शुक्रवार के अंक में 'एक साथ चुनाव पर अनावश्यक आपत्ति' शीर्षक से प्रकाशित अपने आलेख में डा. एके वर्मा ने इस विषय के महत्व को बहुत सारगर्भित रूप में समझाया है। विपक्षी दलों को प्रत्येक विषय राजनीति से जुड़ा हुआ लगता है, इसलिए वे उसका समग्रता में अध्ययन किए बिना ही आपत्ति जताने लगते हैं। एक साथ चुनाव के संदर्भ में कोविन्द समिति ने अपने प्रतिवेदन में कई सार्थक सुझाव दिए हैं। विपक्षी दलों को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि समस्त निर्वाचन एक साथ होने लगेंगे तो राष्ट्र के विकास को गति मिलेगी, क्योंकि बार-बार निर्वाचन से लागू होने वाली आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण विकास के कई कार्य रोकने पड़ते हैं। साथ ही इससे निर्वाचन पर लगने वाले संसाधनों की भी बचत होगी। यहां तक कि राजनीतिक दलों के लिए यह फायदे का सबब होगा। एक साथ चुनाव कराने से अध्ययन एवं अध्यापन कार्य भी अधिक प्रभावित नहीं होगा।

डा. प्रदीप कुमार संघवी, झाबुआ (मध्य प्रदेश)

विपक्ष की नकारात्मक राजनीति

आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) 1971 में इंदिरा गांधी शासन के दौरान भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून था। यह अधिनियम राजनीतिक असहमति को दबाने और राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए खतरा मानी जाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था। मीसा अधिनियम को 1977 में निरस्त कर दिया गया था। राज्यसभा सांसद मीसा भारती का नाम इसी अधिनियम पर उनके पिता लालू प्रसाद यादव द्वारा रखा गया था। लालू प्रसाद यादव तत्कालीन कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे। वैसे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राजद और कांग्रेस आइएनडीआइए के प्रमुख घटक दल हैं। लेकिन आज राज्यसभा सदस्य मीसा भारती, उनके विधायक भाई तेजस्वी यादव, मां राबड़ी देवी 'लैंड फार जाब' मामले के गंभीर आरोपों में सीबीआइ और ईडी जैसी स्वतंत्र व संवैधानिक जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। इसी कारण मीसा भारती आइएनडीआइए की सरकार आने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रियों को जेल में डालने की बात करती हैं। क्या ऐसी बयानबाजी वैमनस्यता, मनभेद, बदले की भावना आदि को परिभाषित नहीं करती। क्या जनसाधारण आइएनडीआइए को इसलिए वोट देगा, जिससे वर्तमान सरकार के मंत्रियों को जेल में डाला जा सके। किसी विपक्षी नेता द्वारा प्रधानमंत्री को हिटलर कहना निश्चित ही सतही व छिछली राजनीति की पराकाष्ठा प्रतीत होती है।

दीपक गौतम, सोनीपत

यह कैसा विरोध

एक साथ चुनाव पर अनावश्यक आपत्ति शीर्षक आलेख में डा. एके वर्मा ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द समिति की ओर से एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रतिवेदन का अध्ययन किए बिना कांग्रेस द्वारा अपनी असहमति जताने के सवालों को लेकर उसे कठघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने राजनीतिक कटुता को लेकर ऐसा अदूरदर्शी कदम उठाया है। बताते चलें कि 18 हजार से ज्यादा पेज की इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव भी करा लिए जाएं। भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने के पूर्व समिति ने 191 दिनों तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल किए नागरिकों के साथ चर्चा करने के बाद रिपोर्ट जमा की है। इधर रिपोर्ट जमा हुई, उधर तुरंत कांग्रेस की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया आ गई। कांग्रेस के स्वर को अन्य विपक्षी दलों का साथ मिला है। विपक्ष की इस व्यवहार के विपरीत कोविन्द समिति ने देश के लोगों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी। जवाब में 81 प्रतिशत लोगों ने समिति के सुझावों के समर्थन में अपनी राय दी और 19 प्रतिशत ने समिति के सुझावों के विरुद्ध अपनी बातें रखीं। चुनाव आयोग ने सरकार को लिखा है 'एक देश एक चुनाव' से कोई परेशानी नहीं होगी।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्वप्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

119 करोड़ रुपये की लागत से कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस हवाई पट्टी पर हाल ही में रात के समय सैन्य हेलीकाप्टर उतारते हुए वायु सेना ने अभ्यास किया है।

आजकल

ज्ञानेंद्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद्

जीवनदायिनी नदियों पर मंडराता संकट

मानव जीवन के लिए नदियां जीवनदायिनी हैं। यही कारण है कि हमारा समाज उनके अस्तित्व को कायम रखने के प्रति निरंतर सजग रहता था। परंतु धीरे धीरे यह सजगता कम होने लगी और उद्योग-धंधों समेत आधुनिक जीवनशैली जनित कारणों से नदियां प्रदूषण का शिकार होने लगीं। वहीं जलवायु परिवर्तन जनित कारणों से भी नदियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट मंडराता दिख रहा है, जिसके प्रति हमें अभी से ही सतर्क हो जाना होगा, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते हैं

नदियों के संरक्षण का प्रयास समय रहते नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब जलराशियां पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगी। फाइल

हमारे देश की ही नहीं, समूचे विश्व की नदियां संकट में हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें कैसे बचाया जाए। कहीं वह पहाड़ों की गोद में ही दम तोड़ती नजर आती हैं, कहीं उनकी जलधाराएं छोटी होती दिखाई देती हैं, कहीं अविरलता के संकट से जूझ रही हैं, कहीं उनके बहाव में कमी का संकट है, कहीं खनन, अवैध कब्जों से हो रहे बहाव में अवरोध से प्रभावित हैं, कहीं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के रसायनयुक्त अपशिष्ट पदार्थों के चलते प्रदूषित हैं। कहीं वह बेतहाशा दोहन से सूख जाने के चलते बीच-बीच में रेत और पत्थर के टीले जैसी नजर आती हैं, कहीं निचले क्षेत्रों में वर्षा के रुझान व ऊंचाई वाली भूमि पर सूखे से प्रभावित हैं, कहीं बेसिन में मौसमी हालात से उनकी स्थिति खराब है, कहीं अनियमित मानसून से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही हैं, कहीं वह जलवायु परिवर्तन के चलते सूख गई हैं और कहीं दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह गर्म हो रही हैं जिससे उनमें आक्सीजन की हानि की दर महासागरों में हो रहे नुकसान की तुलना में कहीं ज्यादा होने से पारिस्थितिकी के भीषण संकट से जूझ रही हैं। कुल मिलाकर उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट मुंह बाए खड़ा है। लिहाजा मजबूत रणनीति, अनुकूल बुनियादी ढांचे और समावेशी नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किए जाने की बेहद जरूरत है।

वस्तुतः जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा मंडरा रहा है। वह चाहे नदियां हों, जंगल हों, मीठे पानी के स्रोत हों, ग्लेशियर हों, बांध हों या फिर विकास कार्य ही क्यों न हों, कोई भी जलवायु परिवर्तन की मार से अछूता नहीं रहा है। अमेजन के जंगल दुनिया को लगभग 20 प्रतिशत आक्सीजन देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं 6400 किलोमीटर लंबी अमेजन नदी जो पेरू से शुरू होकर इक्वाडोर, कोलंबिया होते हुए ब्राजील तक बहती है, अपने मूल स्वरूप की आधी रह गई है। उसका लगभग 50 प्रतिशत पानी सूख गया है। इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से लगभग एक अरब लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

भारत में नदियों का दशा : जहां तक हमारे देश की नदियों का सवाल है, तो इसमें कोई दोराय नहीं कि जिन्हें जीवनदायिनी माना गया, वे आज जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास, खनन, अवैध कब्जे और प्रदूषण के चलते सूख गई हैं, सिकुड़ गई हैं एवं निष्प्राण होती जा रही हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, देश की लगभग 96 प्रतिशत नदियां दस से 100 किमी की ही दूरी तय कर पाती हैं और केवल चार प्रतिशत नदियां ही 500 से लेकर तीन हजार या उससे अधिक की दूरी तय करती हैं। ज्यादातर जलधाराओं का सफर छोटा हो रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार नदियों के सूखने का सिलसिला यदि इसी तरह जारी रहा तो आने वाले कुछ ही दशकों में देश की हालत रेगिस्तान जैसी हो जाएगी। देखा जाए तो देश में लगभग छह सौ नदियां हैं जिनमें से चार सौ से अधिक प्रमुख नदियां हैं। उनमें जल प्रवाह के अनुसार गंगा सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से सिंधु सबसे बड़ी नदी है।

दरअसल हमारे देश में मुख्यतः चार प्रमुख नदी प्रणालियां हैं जिनमें उत्तर भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी और महानदी विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती हैं। इनमें गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, नर्मदा और यमुना प्रमुख बड़ी नदियां हैं। देश की 46 प्रतिशत नदियां प्रदूषित हैं जिनमें गंगा-यमुना सहित देश की कई प्रमुख नदियां भी शामिल हैं। इनमें बीओडी यानी जैविक आक्सीजन की दशा बहुत ही खराब है।

नदियों के सूखने के कारण : बारिश का कम होना, जंगलों की बेतहाशा कटाई और अतिक्रमण आदि नदियों के सूखने के प्रमुख कारण हैं। बहुतेरी नदियों की सहायक नदियां भी धीरे-धीरे विलुप्त हो चुकी हैं। फिर जलवायु परिवर्तन के चलते गंगा, यमुना, घाघरा और कोसी के जलग्रहण क्षेत्र और बहाव में भी कमी आई है। भूजल में भी कमी हो रही है। इसके कारण भूजल से पूरित होने वाली नदियां दिनोंदिन तेजी से सूखती जा रही हैं। इसके अलावा अतिक्रमण, प्रदूषण, उनके मार्ग को मोड़ना और जल संरचनाओं से छेड़छाड़ भी उनके सूखने का कारण है जिस कारण नदियों और धरती दोनों का मिजाज बिगड़ रहा है।

देश की नदियों के बारे में शोध करने पर पता चला है कि देश के उत्तरी राज्यों की 279 नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। इनमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में 55, मध्य प्रदेश में 19, बिहार और केरल में 18-18, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 17-17, राजस्थान में 14, गुजरात, मणिपुर और बंगाल में 13-13 प्रदूषित हैं। यमुना की बदहाली से तो सभी भली-भांति परिचित हैं। देश की 42 प्रतिशत जल जरूरतें पूरी करने वाले उत्तराखंड में पहाड़ों से निकलने वाली नदियां तेजी से सूख रही हैं और अपना स्वरूप खोती जा रही हैं। राज्य की 65 नदियां सूख चुकी हैं और 250 के करीब सूखने के कगार पर हैं। 35 नदियों में बीते 30 वर्षों में पानी 50 से 75 प्रतिशत कम हो गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, गोमती को मिलाकर छोटी-बड़ी लगभग 75 नदियों में से 30 नदियों में गर्मी आते-आते पानी कम हो जाता है या यूं कहें वह निर्जल हो जाती हैं। प्रदेश के पूर्वांचल में नदियां सूखने से जमीन के बंजर होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है।

उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां जैविक आक्सीजन मांग यानी बीओडी के मामले में शीर्ष पर हैं। यहां बीओडी का कई जगह स्तर सामान्य से दस गुणा से भी ज्यादा है। पंजाब में भी यही स्थिति है। गंगा समेत देश की 279 नदियों में से 33 में बीओडी का स्तर 10 गुणा से भी ज्यादा है। गंगा में बीओडी का स्तर सबसे ज्यादा है। यमुना में यह 35, गोदावरी में 31, घग्घर में 27, गोमती में 20, कावेरी में 15, दामोदर और कृष्णा में 12, भवानी और हिंडन में यह 11-11 और मूसा में स्वीकार्य सीमा से बहुत ज्यादा है।

बिहार में आज उत्तर बिहार की 16 और दक्षिण बिहार की आठ समेत कुल 24 नदियां सूख गई हैं। दर्जन भर से ज्यादा में गाद भरा हुआ है। राज्य के लगभग समूचे क्षेत्र में इन 24 नदियों का प्रवाह थम गया है। इनकी लंबाई लगभग तीन हजार किलोमीटर है जिसमें 670 किलोमीटर में जहां नदियां पानी से लबालब रहती थीं, आज वे गाद भरी हुई हैं। राज्य में नदियों की हालत बेहद खराब है। नदियां छोटे-छोटे जलाशय और जलस्रोत में तब्दील होती जा रही हैं। बागमती और बूढ़ी गंडक सूखने के कगार पर है। कई नदियों में पानी का बहाव पूरी तरह से ठहर गया है। झारखंड में भी छोटी-बड़ी लगभग 91 नदियां हैं। यहां दामोदर और स्वर्णरेखा दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो उद्योग-धंधों की वजह से बेहद प्रदूषित हैं। विशेषज्ञों की मानें तो दामोदर का कुछ बरस पहले पानी प्रदूषण के चलते काला तक हो गया था। विडंबना यह है कि इनकी प्रदूषण मुक्ति के बारे में सरकार मौन है। उनकी इस बाबत कोई योजना ही नहीं है।

नदियों की प्रकृति के अनुरूप प्रबंधन की व्यवस्था

हाल ही में विश्व की 800 नदियों पर एक अध्ययन किया गया है जिसमें यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की 87 प्रतिशत नदियां गर्म हो रही हैं और 70 प्रतिशत नदियों में आक्सीजन की कमी हो रही है। ये दुष्परिणाम बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। एक आकलन के अनुसार, आने वाले बरसों में यदि यही हाल रहा तो नदियों के तंत्र में आक्सीजन इतनी कम हो जाएगी जिससे मछलियों समेत कई प्रजातियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दरअसल जलवायु के गर्म होने के चलते महासागर तो गर्म हो ही रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि नदियों के साथ भी होगा। इस अध्ययन में नदियों के तापमान में बदलाव और आक्सीजन कम होने की दर की पानी की गुणवत्ता और जलीय जीवों तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहे दुष्परिणाम का राजफाश हुआ है। अब यह जगजाहिर है कि हमारे देश की ही नहीं, समूची दुनिया की दस बड़ी नदियों पर भीषण खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में कमोबेश सभी नदियां अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। इसलिए यह जरूरी है कि नदियों को बचाने के लिए दुनिया भर में ठोस और स्थायी उपाय किए जाएं।

इस बारे में हमें एशियाई विकास बैंक और पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फार क्लाईमेट इंपैक्ट रिसर्च की रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में हो रहे बदलाव का असर हिमालय पर भी पड़ेगा। आने वाले वर्षों में हालात और भयानक होंगे। दक्षिण एशियाई भौगोलिक क्षेत्र की ज्यादातर नदियां 80 प्रतिशत ग्लेशियरों पर निर्भर हैं। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से नदियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रभावित हो रही है। परंपरागत जलस्रोतों की अनदेखी और नदियों में गाद की समस्या का समाधान करने में नाकामी इसका सबसे बड़ा कारण है। जबकि नदियों में गाद की समस्या के निदान हेतु कंप्रिहेंसिव सिल्ट पालिसी बनाने और नदी प्रबंधन की मांग बरसों से पर्यावरणविद एवं नदी जल विज्ञानी करते रहे हैं। यही नहीं, वन विहीन हो चुके नदियों के जलागम को वनाच्छादित करने में भी सरकार की विफलता जगजाहिर है। इससे एक ओर जहां नदियों के जल बहाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती, वहीं दूसरी ओर वनाच्छादित तट प्राकृतिक तौर पर बांधों के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते। अब समय की मांग है कि नदियों की प्रकृति का सूक्ष्म विश्लेषण-अध्ययन किया जाए और उसी के तहत नदी प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। इसके सिवाय इसका कोई हल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में सरकार और समाज दोनों के ही ईमानदारी से सामूहिक प्रयास से ही कुछ बात बनने की उम्मीद की जा सकती है।

(ज्ञानेंद्र रावत)

खरी-खरी

बुझो तो जानें!

विनोद कुमार विक्की

ब्रह्मांड में वह कौन सा अद्भुत, अलौकिक, अतुलनीय गोला खंड है जहां के नेता, जनता को सक्षम और सबल बनाने के बजाय मुफ्तखोर और आश्रित बनाने के नाम पर लोकतांत्रिक चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं? आत्मनिर्भर बनाने से ज्यादा मुफ्त वाली योजनाएं लाई जाती हैं। जहां आम जनता मेहनत का फल खाने के बजाय मुफ्त का लालीपाप चूसने के लिए अपने प्रधान का चयन करती है। जहां आरक्षण के जहाज पर बैठकर लोग उड़ान भरने को लोलुप रहते हैं। जहां के अति व्यस्तजीवी मानव जेसीबी से मिट्टी खुदाई को घंटों देखने के लिए बहुमूल्य समय निकालते हैं। मोबाइल और नेट पैक पर देर रात समय गुजारने वाला मोबाइल जीवी स्वयं को व्यस्त कहते हैं। जहां अदृश्य हूर और जन्नत के लिए कुछ लोग भाई को चारा बनाकर भाई 'चारा' निभाते हैं। जहां की कुछ जनता शत्रु देश की जयकार और राष्ट्रगान का तिरस्कार कर स्वयं को धन्य समझती है। जहां चर अचर के स्वामित्व से इंसान के जीवित अथवा मृत्यु होने का साक्ष्य कागज तय करता है।

जहां 40 वर्षीय प्रौढ़ छात्र एवं युवा कहलाता है, 30 वर्षीय युवा आइएएस अधिकारी बनकर जिला नहीं चला सकता, किंतु 72 साल वाला चिर युवा देश चला सकता है। जहां चुनावी वादों और जनता की उम्मीद पर सरकार चलती है। जहां रील लाइफ यथा सीआइडी और क्राइम सीरियल में एपिसोड के अंत तक पुलिस अपराधी को तलाशती रह जाती है, जबकि रीयल लाइफ में उस गोला खंड पर संत से संतरी तक की जानकारी में रहने के बावजूद अपराधी खुलेआम शान से विचरण करता है। जहां सरकारी कर्मचारी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हास्पीटल का तथा गैर सरकारी कर्मचारी, सरकारी विद्यालय एवं सरकारी अस्पताल का लाभ उठाते हैं। जहां पढ़ा लिखा व्यक्ति कार्यालय चलाता है और अनपढ़ राज्य चलाने में सक्षम होता है।

हमें पता है कि आप बुद्धिजीवी हैं, प्रश्नों को पढ़ने के साथ ही दिमाग में उत्तर बताते गए होंगे। चलिए अगली पहेली के साथ आपके दिमाग की बत्ती जलाने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।

पोस्ट

यह कोई संयोग नहीं है, जो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट के आरोपित बंगाल से पकड़े गए। आतंकियों को हमेशा 'सुरक्षित ठिकानों' की तलाश रहती है।
सुमंत @sumantkabir

बिहार के बहुत से बंधु कहते हैं कि यदि बिहार के लोग दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई छोड़ दें तो ये महानगर ठप पड़ जाएंगे। हम कहते हैं ठप पड़ जाने दो इन शहरों को, वापस आ जाओ और ठप पड़े बिहार को चलाओ।
नितिन नीरा चंद्रा @nitinchandra25

60 प्रतिशत और कुछ राज्यों में तो 90 प्रतिशत तक मुसलमान ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं और लिखकर बताते हैं कि जुलाहा, कसाई, धुनिया, कुंजड़ा, चूड़ीहार जाति के हैं। सबको अपनी पुरानी जाति याद है। मुसलमान होने का मतलब जाति से आजाद होना नहीं है।
दिलीप मंडल @Profdilipmandal

भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ताओं की जुबान कैसे बदल जाती है? गजब के मौकापरस्त लोग हैं। ये सारे के सारे अपना करियर बनाने आए थे। इनका न देश से कुछ लेना-देना है और न ही इनकी कोई विचारधारा है। करियर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी।
आशुतोष @ashutosh83B

बिहार डायरी

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं, सिर्फ मोदी का गुणगान

यह आश्चर्य का विषय है कि राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ रहे पक्ष और विपक्ष के अधिसंख्य उम्मीदवारों के पास अपनी किसी उपलब्धि के नाम पर वोट मांगने का साहस नहीं है। राजग के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उधर, महागठबंधन के उम्मीदवार नीतीश की अगुआई वाली राज्य सरकार के उस 17 महीने की उपलब्धियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिसमें राजद और कांग्रेस की भागीदारी थी। सबसे बड़ी उपलब्धि यह कि इन्हीं 17 महीनों में करीब चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं, इनमें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी थे।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राजग के 39 उम्मीदवारों को सफलता मिली थी। इनमें से 12 सांसदों को राजग ने इस बार बेटिकट कर दिया। भाजपा, जदयू और लोजपा के चार-चार सांसद बेटिकट हुए। इनमें से कुछ दूसरे दलों की शरण में जा रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दल में रह कर नेतृत्व की कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें राज्यसभा, राजभवन, विधान परिषद या मनोनयन के किसी अन्य पद की आकांक्षा है। इनमें रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी हैं, जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दे दिया था। नफा-नुकसान जोड़ फिर मोदी की शरण में आ गए हैं।

राजग के 39 में से 27 पुराने सांसद मैदान में हैं। एक-दो को छोड़ शेष सांसदों को कामकाज का हिसाब देना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में तो इन्हें क्षेत्र भ्रमण में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उनसे पूछा जाता है कि पांच साल पहले के वादों का क्या हुआ? कोरोना महामारी थी। मगर इन दिनों यह क्षेत्र से अनुपस्थित रहने वाले सांसदों का बचाव भी कर रही है। सांसदों को यह कहने पर थोड़ी राहत मिल रही है कि कोरोना के कारण उनकी सेवा में थोड़ी त्रुटि रह गई थी। महामारी की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी गई सुविधाओं का विवरण देकर भी ये अपने लिए सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रति व्यक्ति पांच किलो राशन, हर घर बिजली, नल का जल, कृषि अनुदान, पक्का आवास, मुख्य सड़कें, अस्पताल, पुल-पुलियों सहित सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाओं को अपनी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता यह पूछ कर सांसद के दावे को अस्वीकार कर दे रही है कि इसमें आपका क्या योगदान है। ये सभी योजनाएं केंद्र- राज्य सरकार की हैं, सबके लिए हैं, इसका लाभ किशनगंज की जनता को भी मिल रहा है, जहां के सांसद कांग्रेसी हैं।

सरकार के कामकाज पर राजग उम्मीदवार के लिए वोट की मांग। फाइल

असल में सांसदों से अधिक प्रश्न उनके व्यवहार को लेकर पूछे जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के कारण गांवों की बुनियादी नागरिक सुविधाएं लगातार सुधर रही हैं। नाली और गली तक का निर्माण राज्य सरकार की योजनाओं से हो रहा है। अधिक परेशानी इस प्रश्न पर हो रही है कि चुनाव जीतने के बाद कितनी बार क्षेत्र में आए। राजग के उन सांसदों की संख्या भी कम नहीं है, जो चुनाव जीतने के पांच साल बाद ही अपने संसदीय क्षेत्रों के सुदूर इलाके में दूसरी बार नजर आ रहे हैं। जदयू के एक सांसद के बारे में रिकार्ड में दर्ज है कि कार्यवाही के समय लोकसभा में उनकी उपस्थिति 35 प्रतिशत से कम थी। संसद में प्रश्न पूछने और बहस में हिस्सा लेने में भी इनकी भूमिका ऐसी नहीं रही, जिसका उल्लेख किया जाए।

इन प्रश्नों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को भी दो चार होना पड़ता है। महागठबंधन के दलों ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, उनमें कुछ पूर्व सांसद भी हैं। इनसे उनके कार्यकाल के कामकाज के अलावा यह भी पूछा जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्षेत्र से संबंध क्यों तोड़ लिया? पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा चुनाव में राजद के बांका से उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव के टिकट का यह कह कर विरोध किया गया कि 2019 में हारने के बाद वह क्षेत्र से कट गए। विरोध करने वाले राजद के कार्यकर्ता थे। कुछ ऐसी ही शिकायत इस क्षेत्र के वर्तमान जदयू सांसद गिरिधारी यादव के बारे में भी की गई थी। दोनों आमने-सामने हैं।

ऐसे में कोई सोच सकता है कि नाराज लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे। यह नहीं होता है। पिछले कई चुनावों में वोटरों की नाराजगी का प्रभाव मतदान के दिन नजर नहीं आया है। वोटरों का यही भाव उम्मीदवारों को जीतने के बाद क्षेत्र से विमुख कर देता है। इस बार भी यही हो रहा है। राजग के उम्मीदवारों को पता है कि लोग केंद्र में नरेन्द्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उन्हें वोट देंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवारों का आकलन है कि मोदी और समग्रता में राजग के विरोधी मतदाताओं का समूह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वोट देगा। इसका प्रभाव चुनाव प्रचार पर भी पड़ रहा है। कोई आदमी बिहार की यात्रा करे तो उसे प्रचार से यह पता नहीं चलेगा कि सप्ताह भर बाद यहां के चार लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान होगा। प्रचार की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कौन किसको वोट देगा, यह निर्णय हो चुका है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या संदेशखाली मामले की सीबीआइ जांच आवश्यक थी?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
टेस्ला के भारतीय बाजार में आने से इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कई धुरंधर आजकल गए घरों में बैठ,
नव पीढ़ी के नौजवां बना रहे हैं पैठ।
बना रहे हैं पैठ कि जैसे देवी कंगना,
कंटक बोएं जाय वहां राजा के अंगना।
नया खून नव शक्ति घूमती दिखती घर-घर,
घर बैठे थक हार आजकल कई धुरंधर।
– ओमप्रकाश तिवारी

राष्ट्रीय राजमार्ग

डा. लक्ष्मी शंकर यादव
पूर्व प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान विषय

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रहरी

देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए भारतीय वायु सेना निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित अनेक हवाई पट्टियों पर कई लड़ाकू विमान उतारे गए हैं

चीन और पाकिस्तान की रणनीति में बदलाव के कारण भारत की सामरिक तैयारी यही है कि युद्ध की स्थिति में वह दोनों मोर्चों पर निपट सके। इसके लिए वायु सेना उन राष्ट्रीय राजमार्गों को रनवे के रूप में आजमा रही है जो युद्ध की स्थिति में काम आ सकें। देश के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय वायु सेना लगातार ऐसे कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय वायु सेना ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहड़ा इलाके में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की साढ़े तीन किलोमीटर लंबी आपातकालीन हवाई पट्टी का रनवे के रूप में उपयोग करते हुए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों व हेलीकाप्टर उतारकर नौ ट्रायल परीक्षण किए। इन परीक्षणों के समय सड़क यातायात को वैकल्पिक रास्तों की ओर मोड़ दिया गया था और हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था।

विदित हो कि पाकिस्तान और चीन की चालों एवं युद्ध संबंधी स्थितियों से मुकाबले को ध्यान में रखकर ही अनंतनाग के बिजबेहड़ा हाइवे पर इस हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। पाकिस्तान या चीन के विरुद्ध इस हवाई पट्टी से वायु सेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने में बहुत कम समय लगेगा। अत्यंत कम समय में भारतीय वायु सेना के फाइटर विमान शत्रु के विमानों का मुकाबला करेंगे। उड़ान भरने के बाद मात्र तीन मिनट में ये पाकिस्तानी सीमा पर और पांच मिनट में पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर पहुंच जाएंगे।

इस अभ्यास के बाद जम्मू-कश्मीर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्तमान में आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा देश के तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में उपलब्ध है। इस अभ्यास में अमेरिका निर्मित चिनूक हेलीकाप्टर को शामिल किया गया। चिनूक को हाल ही में वायु सेना में शामिल किया गया है। इस परीक्षण में दो चिनूक हेलीकाप्टर, रूस निर्मित एक एमआइ-17 और दो उन्नत हल्के हेलीकाप्टर जम्मू-श्रीनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग के वानपोह-संगम मार्ग पर उतारे गए थे। यह राजमार्ग कश्मीर को देश के शेष हिस्सों से जोड़ता है। इस हवाई पट्टी का रणनीतिक उद्देश्यों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा।

बाड़मेर में अभ्यास : इसी तरह आठ अप्रैल को भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से मात्र 40 किमी की दूरी पर स्थित एयर स्ट्रिप पर वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। यह अवसर था वायु सेना के तीन दिवसीय अभ्यास के बाद हवाई पट्टी के हैंड ओवर का। इस कारण इस हवाई पट्टी पर वायु सेना ने छह अप्रैल को ही अपना डेरा डाल दिया था। अभ्यास के तहत आठ अप्रैल को इस हवाई पट्टी पर तेजस लड़ाकू विमान उतारा गया। इसके बाद जगुआर लड़ाकू विमान व सी-295 तथा एएन-32 जैसे परिवहन विमान उतारे गए। यह अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह हवाई पट्टी राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाइवे-925 ए पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस हवाई पट्टी का लोकार्पण नौ सितंबर 2021 को किया गया था। इसका उद्घाटन परिवहन विमान सी-130 जे हरक्यूलिस की आपातकालीन लैंडिंग अभ्यास से किया गया। इस दौरान सुखोई-30 एमकेआइ लड़ाकू विमान, सैन्य परिवहन विमान एएन-32 और एमआइ-17 वी हेलीकाप्टर ने भी आपातकालीन लैंडिंग की थी। इस अभ्यास के सफलतापूर्वक संपन्न होने से यह माना गया कि अब देश की सामरिक जरूरतों के हिसाब से यह नया प्रयोग रणनीतिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

राजस्थान में इसी सप्ताह नेशनल हाइवे पर उतारा गया वायु सेना का मालवाहक विमान। फाइल

वस्तुतः राष्ट्रीय राजमार्गों पर रनवे सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में बनाया गया था। इसके बाद उत्तर कोरिया, ताइवान, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया में बनाए गए। स्वीडन में पहला रनवे 1949 में शुरू हो गया था। पोलैंड ने अपने यहां वर्ष 2003 में हाइवे स्ट्रिप तैयार की थी। आस्ट्रेलिया में हाइवे के कई हिस्सों को रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दक्षिण कोरिया में भी कई जगहों पर हाइवे पर रनवे बनाए जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इस श्रेणी में अब भारत भी शामिल हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित होने वाली ऐसी हवाई पट्टियों की संख्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से स्वागतयोग्य है।

****

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/sharewithpride (sharewithpride)

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं।
-नेल्सन मंडेला

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक निजी स्कूल की बस के साथ हुआ दर्दनाक हादसा त्रासद तो है ही, व्यवस्थागत लापरवाही का भी घनघोर उदाहरण है। प्रशासन इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ऐसे हादसे दोबारा न हों, यह सुनिश्चित किया जाना भी उतना ही जरूरी है।

आपराधिक लापरवाही

दिल्ली से सटे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल स्थित उन्हाणी गांव के नजदीक एक निजी स्कूल की बस के पेड़ से टकराने से हुआ दर्दनाक हादसा जितना दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासद है, उतना ही व्यवस्थागत लापरवाही का घनघोर उदाहरण भी है। बताया जा रहा है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी और 43 बच्चों को लेकर बेहद तेज गति से बस को चला रहा था। एक मोड़ के पास चालक का नियंत्रण खो गया और बस पेड़ से टकराकर पलट गई। इस हादसे में छह बच्चों की मौत हो गई और 34 अन्य घायल हो गए, जिससे पता चलता है कि दुर्घटना किस कदर गंभीर थी। उस भयावह स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है, जब बेकाबू बस का ड्राइवर तो कूदकर भाग गया, जबकि असहाय बच्चे खिड़कियों से बाहर गिरते जा रहे थे। प्राप्त जानकारियों के अनुसार, उस बस का छह साल से न तो फिटनेस टेस्ट कराया गया था, न ही रोड टैक्स भरा गया था। यही नहीं, करीब एक महीने पहले ही सड़क पर चलने लायक न पाए जाने की वजह से बस का करीब 15 हजार रुपये का चालान भी हुआ था। फिर भी अगर बस सड़क पर चल रही थी, तो यह स्पष्ट रूप से आपराधिक कृत्य ही है, जिसे महज लापरवाही कह कर जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था कि स्कूली बच्चों को घर से स्कूल तक सुरक्षित लाने व ले जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसमें नियमों के खिलाफ चल रही बसों की जांच किए जाने का भी उल्लेख था। जाहिर है, महेंद्रगढ़ हादसा स्कूल प्रशासन और परिवहन विभाग की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा करता है। स्कूलों में आज बसों, छोटी वैन या ई-रिक्शे में क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाने के दृश्य पूरे देश में आम हैं, जो महेंद्रगढ़ जैसे हादसों की पुनरावृत्ति की आशंका से डराते तो हैं ही, यह भी दिखाते हैं कि स्कूलों तक बच्चों का सफर कितना असुरक्षित हो गया है। शीर्ष अदालत,

सरकारों व सीबीएसई द्वारा भी स्कूली बसों को लेकर समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन इसे लेकर स्कूल प्रशासन व अभिभावकों की उदासीनता भी उतनी ही हैरान करने वाली है। ऐसे हादसों के बाद जैसा कि अमूमन होता है, प्रशासन की ओर से इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए व्यवस्थागत सुधारों को पूरी कड़ाई से तत्काल लागू किया जाना भी जरूरी है।

तमिलनाडु की सियासत के नए संकेत

मतदाता दोनों द्रविड़ पार्टियों से निराश हैं-चाहे द्रमुक हो या अन्नाद्रमुक। वे अब एक वैकल्पिक पार्टी को आजमाना चाहते हैं। राज्य और जिला स्तरीय दलों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि मतदाताओं में सिनेमा संस्कृति के प्रति निराशा बढ़ रही है और दक्षिण समर्थक भावनाओं का विकास हो रहा है।

आर राजगोपालन
वरिष्ठ पत्रकार

तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं के साथ भाजपा वहां धुआंधार प्रचार कर रही है, जबकि द्रमुक और कांग्रेस पूरी तरह से एमके स्टालिन और राहुल गांधी पर निर्भर हैं। तीन धड़ों में बंट चुकी अन्नाद्रमुक ने भी अपने स्थानीय नेताओं को राज्य के दौरे में व्यस्त रखा है। एडाप्पडी पलानीस्वामी अन्नाद्रमुक के स्टार प्रचारक हैं।

द्रविड़ पार्टियों को हिंदू समर्थक भाजपा से कठिन चुनौती मिल रही है। पहली बार राज्य में 70 वर्षों से बारी-बारी शासन में रहे द्रमुक और अन्नाद्रमुक, दोनों द्रविड़ दलों को भाजपा और सिने अभिनेता विजय द्वारा हाल ही में गठित सीमन नाम तमीझर काची पार्टी से खतरा महसूस हो रहा है। तमिलनाडु में एक ऐसा वर्ग उभरा है, जो मोदी के तीसरे कार्यकाल के पक्ष में है।

तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के भाषण और घोषणापत्रों से यही संकेत मिलता है कि पार्टियां 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर लोकसभा चुनावों की तुलना में ज्यादा जोर दे रही हैं। तमिलनाडु की ये राज्य और जिला स्तरीय पार्टियां चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी का शासन बिल्कुल खत्म होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना प्रवासी पक्षियों से की है, जो चुनावी मौसम में तमिलनाडु आते हैं।

विभिन्न दलों के नेता एक-दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीन सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि 'द्रमुक की विचारधारा राष्ट्र विरोधी है। पिछले 10 वर्षों में राजग सरकार तमिलनाडु के मछुआरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राजग सरकार तमिलनाडु के पांच मछुआरों की जान बचाकर उन्हें भारत लाई, जिन्हें श्रीलंका की अदालत

ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।' उन्होंने आगे कहा कि 'द्रमुक के एक नेता का कहना है कि यह चुनाव मोदी को देश से बाहर भेजने के लिए है, लेकिन यह चुनाव भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति और नशीले पदार्थों के खतरे को देश से बाहर भेजने के लिए द्रमुक की राष्ट्र-विरोधी विचारधारा को खत्म करने के लिए है।'

यदि नेताओं के भाषणों का विश्लेषण किया जाए, तो उससे कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। एक, यदि द्रमुक सभी 39 सीटें जीत जाती है, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि उसके लिए 2026 का मार्ग सुरक्षित है और गठबंधन कायम रहेगा।

दूसरा, यदि अन्नाद्रमुक 8-10 सीटें जीत जाती है और भाजपा गठबंधन पांच से आठ सीटें जीत जाता है, तो यह द्रमुक के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान को दर्शाएगा। ऐसे में स्टालिन के सामने अपनी पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती पैदा होगी। जाहिर है, द्रमुक को तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो जाएंगी।

तीसरा, यदि केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बना लेती है, तो निश्चित रूप से भाजपा द्रमुक को खत्म करने के लिए वैसा ही अभियान चलाएगी, जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा और आप के खिलाफ चलाया। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने स्टालिन सरकार को रेत माफिया, ड्रग माफिया और तुष्टीकरण का एजेंट बताया है।

वर्ष 1967 से राज्य की राजनीति पर नजर रखने के नाते इन पंक्तियों के लेखक का मानना है कि मतदाता दोनों द्रविड़ पार्टियों से निराश हैं-चाहे द्रमुक हो या अन्नाद्रमुक। वे अब एक वैकल्पिक पार्टी को आजमाना चाहते हैं। राज्य और जिला स्तरीय दलों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि मतदाताओं में सिनेमा संस्कृति के प्रति निराशा बढ़ रही है और दक्षिण समर्थक भावनाओं का विकास हो रहा है। ऐसे में हैरानी नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा फॉर्मूले पर तमिलनाडु पर कब्जा करने के लिए आक्रामक रुख अपनाएंगे। इसके लिए तमिलनाडु में बुनियादी संरचनाओं के निर्माण और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे। नशे के कारोबार और खनन माफिया पर अंकुश लगाने के साथ वह विदेशी निवेशकों को भी इसके लिए आकर्षित कर सकते हैं। एक विदेशी कंपनी सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में दक्षिणी राज्यों में निवेश करना चाहती थी, लेकिन सामाजिक अशांति और कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण अचानक उसे पश्चिमी राज्यों का रुख करना पड़ा।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विदेशी शक्तियां, खासकर चीन और पाकिस्तान दक्षिणी राज्यों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही हैं। चीन ने कोलंबो में अपना खुफिया पोत तैनात किया था, लेकिन द्रमुक के 38 सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में हुई बहस में हिस्सा नहीं लिया। भाजपा के प्रदेश प्रमुख के अन्नामलाई ने द्रमुक सांसदों के रुख पर सवाल उठाया है।

एमके स्टालिन ने अपने पिता करुणानिधि की मृत्यु के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा है। उधर पलानीस्वामी ने भी कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर अपना अधिकार बरकरार रखा है। मगर अन्नाद्रमुक लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं है, वह 2026 के चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है। मगर द्रमुक के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है। द्रमुक जानती है कि अगर भाजपा केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाती है, तो राष्ट्रीय राजनीति में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। इसलिए 2026 के चुनावों में सत्ता पर दावेदारी के लिए द्रमुक ज्यादा लोकसभा सीटें जीतना चाहती है।

द्रमुक और अन्नाद्रमुक एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चातिवु, वंशवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर आक्रामक ढंग से राज्य में पैठ बनाई है। भाजपा पहली बार राज्य में वैकल्पिक मॉडल शासन के लिए मतदाताओं को प्रेरित कर रही है। यही वजह है कि द्रमुक और अन्नाद्रमुक, दोनों भाजपा के हिंदुत्व समर्थक और द्रविड़ विरोधी आक्रामक प्रचार अभियान से परेशान है। राज्य के मतदाता चाहते हैं कि घोषणापत्रों को अमल में लाया जाए। हालांकि तमिलनाडु के मतदाताओं की छवि पैसे लेकर वोट देने की रही है, लेकिन इस बार वही मतदाता नेताओं से कड़े सवाल पूछ रहे हैं। यह एक नया रुझान है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

परमहंस योगानंद

हमें अपने मन को इन उदासी भरे और डरावने दृश्यों में उलझाना नहीं चाहिए। जीवन रूपी नाटक से सबक सीखिए और स्वयं को मुक्त कीजिए। इस जीवन की छाया के पीछे परमात्मा का अद्भुत प्रकाश विद्यमान है।

जहां परमात्मा है, वहां न डर है, न दुख

आज सारे संसार में जो अव्यवस्था और आपदाएं आप देख रहे हैं, उनका एकमात्र कारण मनुष्य द्वारा ईश्वर के सिद्धांत के विपरीत जीवन-शैली अपनाना है। व्यक्तियों और राष्ट्रों को संभावित संपूर्ण विनाश से बचाया जा सकता है, किंतु तभी, जब वे ईश्वर द्वारा बताए गए बंधुत्व, सहयोग तथा ज्ञान का अंतरराष्ट्रीय विनिमय करने के लिए तत्पर हो जाएं। मेरा विश्वास है कि एक ऐसा समय आएगा, जब सब लोग उच्च स्तर पर एक-दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे और भौगोलिक सीमाएं टूट जाएंगी। हम पृथ्वी को अपना राष्ट्र पुकारेंगे; और हम न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा स्वार्थ की भावना को त्याग कर सभी उपयोग की वस्तुओं का वितरण पूरे विश्व में मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार करेंगे। लेकिन समानता को बलपूर्वक शक्ति के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता; यह मनुष्य के अंतस्थल से स्वयं आनी चाहिए। एक-दूसरे से प्रेम का व्यवहार करते हुए पारस्परिक सम्मान और समझ के साथ हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। ईश्वर वस्तुतः प्रेम है; सृष्टि के लिए उनकी संपूर्ण योजना का आधार केवल दिव्य प्रेम है। प्रत्येक महान संत ने, जिन्होंने परम सत्य को प्राप्त किया, यही कहा कि पूरी सृष्टि में एक दिव्य योजना संचालित हो रही है, जो बहुत सुंदर और आनंद से परिपूर्ण है। जहां परमात्मा है, वहां न डर है, न दुख। निर्भय होने का तात्पर्य है कि ईश्वर में, उनकी शक्ति और संरक्षण में, उनके न्याय में, उनके ज्ञान में, उनकी करुणा में, उनके प्रेम में, उनकी सर्वव्यापकता में पूरी आस्था और विश्वास रखना। डर मनुष्य को उसकी आत्मा की अदम्य शक्ति से वंचित कर देता है। जब असहनीय चुनौतियों का पहाड़ आप पर टूट पड़े, तब साहस और सूझबूझ न खोएं। अपनी सहज बुद्धि तथा ईश्वर में आस्था को सक्रिय रखिए, और उस संकट से बच निकलने का रास्ता खोजने का प्रयास कीजिए, आपको मार्ग मिल जाएगा। जब भी जीवन में अंधेरे पथ पर चलना पड़े, तो ईश्वर को अपना दीप बना लीजिए। आपके जीवन के तमस आच्छादित सागर में राह दिखाने वाले ध्रुवतारा वे ही हैं। हमेशा याद रखें कि यह विध्वंसक शक्ति अंतिम विजेता नहीं है। इतिहास के आरंभ से ही शुभ और अशुभ के बीच में संघर्ष होता रहा है। अशुभ और अमंगल को रोकने के लिए धर्म युद्ध की आवश्यकता होती है। जो लोग धर्म युद्ध करते हैं, वही जीतते हैं। जब प्रत्येक आत्मा भेदभाव वाले विचारों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सूझबूझ प्राप्त कर लेगी, तब विश्व के सारे संकट खत्म हो जाएंगे और विश्वव्यापी बंधुत्व स्थापित हो जाएगा।

हमें अपने मन को इन उदासी भरे और डरावने दृश्यों में उलझाना नहीं चाहिए। जीवन रूपी नाटक से सबक सीखिए और स्वयं को मुक्त कीजिए। इस जीवन की छाया के पीछे परमात्मा का अद्भुत प्रकाश विद्यमान है। यह सारा ब्रह्मांड परमात्मा की असीम सत्ता का मंदिर है।

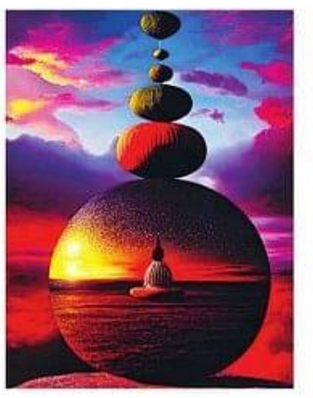

एक ही दुनिया के वासी...

सूत्र

तकनीकी आविष्कारों ने हम सभी को निकट ला दिया है, जैसा पहले कभी संभव नहीं था। हम सभी एक ही दुनिया के वासी हैं, जो एक परमेश्वर के अधीन संचालित है। इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य आदर्श वैश्विक नागरिक बन सकते हैं, जो हर अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

दूसरा पहलू

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 से 2050 के बीच सालाना ढाई लाख मौतें होंगी।

जलवायु परिवर्तन कितने लोगों की जान लेगा?

जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहीं और भविष्य में होने वाली मौतों के आंकड़ों पर अंतहीन बहस चल रही है। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने बीबीसी को बताया कि अगर वैश्विक तापमान औद्योगिक युग के पहले के तापमान से दो डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया, तो अमीर लोग पूरी दुनिया में एक अरब से भी अधिक गरीबों की मौत के जिम्मेदार होंगे। बेशक इस दावे की सत्यता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पर यह जरूर है कि मौत का आंकड़ा जब ज्यादा बताया जाता है, तभी लोग चौंकते हैं। अन्यथा जलवायु परिवर्तन से निरंतर हो रही मौतों पर बहुत चिंता नहीं है।

डेविड वैलेस वेल्स

हाल ही में *नेचर मेडिसिन* में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के जीवविज्ञानी कोलिन कार्लसन ने एक दशक पुराने फॉर्मूले से गणना करके बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2000 से अब तक 40 लाख लोग कुपोषण, बाढ़, डायरिया, मलेरिया और दिल की बीमारियों से मरे हैं। पिछले करीब 25 साल में इतने लोग अगर जलवायु परिवर्तन के कारण मारे गए हैं, तो यह चिंता की बात है।

हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2014 में जारी एक अध्ययन में कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 से 2050 के बीच सालाना ढाई लाख मौतें होंगी। 'द प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ते तापमान के कारण भारत में सालाना एक लाख और चीन में सालाना डेढ़ लाख लोग मर रहे हैं। इस सदी के अंत तक बढ़ते तापमान से होने वाली मौतों का आंकड़ा कई गुना बढ़ जाएगा। ध्यान देने की बात है कि बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन का सिर्फ एक लक्षण है। प्रदूषण, सूखा, बाढ़, बीमारियों और अनाज की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा तो इसमें शामिल ही नहीं है। इसी संस्था के अध्ययन के मुताबिक, प्रदूषण से चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका में होने वाली मौतों का सालाना आंकड़ा लाखों में है। जाहिर है, बढ़ता तापमान और बढ़ता प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के सबसे स्पष्ट लक्षण हैं।

दुनिया भर में होने वाली मौतों में प्रदूषण से होनेवाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और विशेषज्ञों का आकलन है कि सदी के अंत तक ज्यादातर मौतें प्रदूषण के कारण ही होंगी। बल्कि जैसा कि पर्यावरणविद कहते हैं, कि जलवायु परिवर्तन का नतीजा पूरी दुनिया में भीषण त्रासदी के रूप में आ सकता है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी।

'द प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ते तापमान के कारण भारत में सालाना एक लाख और चीन में सालाना डेढ़ लाख लोग मर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2000 से अब तक 40 लाख लोग कुपोषण, बाढ़, डायरिया, मलेरिया और दिल की बीमारियों से मरे हैं, जो चिंता की बात है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

उत्पादन में वृद्धि

मारुति सुजुकी ने तीन करोड़ उत्पादन इकाइयों का आंकड़ा हासिल किया, जो दुनिया भर में सुजुकी बेस के बीच सबसे तेज है।

स्रोत : Company

प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से अपनी अर्जित आय का कुछ अंश गरीबों, बेसहारा लोगों और बीमारों की सेवा में खर्च करना चाहिए।

अमल भी करें

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

स्वामी रामानंद सरस्वती गांवों और नगरों में पहुंचकर धर्म, सदाचार, कर्तव्यपालन व भक्ति का प्रचार किया करते थे। एक बार काशी में कोलकाता के एक विद्वान देवीचरण गांगुली पत्नी और पुत्र के साथ उनके सत्संग के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने अपना अब तक का जीवन विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन एवं सत्संग में बिताया है। देश के सभी तीर्थों की यात्राएं की हैं, किंतु मुझे अब तक सुख-शांति की अनुभूति नहीं हुई। इसका क्या कारण है?

स्वामी रामानंद जी ने पूछा, आपने धर्मशास्त्रों में जो भी पढ़ा, क्या उसमें से कुछ बातों का पालन करने का प्रयास किया है? प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से अपनी अर्जित आय का कुछ अंश गरीबों, बेसहारा लोगों और बीमारों की सेवा में खर्च करना चाहिए। सात्विक जीवन जीना चाहिए। आपने क्या कभी इन नियमों का पालन किया है?

देवीचरण गांगुली स्वामी जी के वचन सुनकर चुप बैठे रहे। स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार औषधि खाने से ही लाभ होता है, उसी प्रकार जब तक पढ़ी-सुनी बातों पर अमल नहीं करेंगे, उनका लाभ नहीं होगा। तीर्थयात्रा के फेर में न पड़कर धर्म के सारभूत तत्वों को जीवन में उतारने में अपना समय बिताएं। इन्हीं कर्मों से आपको शांति मिलेगी।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 01 फरवरी, 1955

श्रमदान करके लौट रहे अधिकारी घायल

२५ श्रमदानकारी अफसर घायल

लखनऊ, ३१ जनवरी। यहां से पांच मील दूर लीलमाया नामक स्थान पर श्रमदान करके जब तामीर विभाग के अफसर एक ट्रक से वापिस आ रहे थे तो वह एक बिजली के खंभे से टकरा गया जिसके फल-स्वरूप २५ अफसर घायल

लखनऊ से पांच मील दूर लीलमाया नामक स्थान पर श्रमदान करके कुछ अफसर जिस ट्रक से लौट रहे थे, वह बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसमें 25 अधिकारी घायल हो गए। घायलों को बलरामपुर अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

चुनावी दौर में जहरीली शराब का धंधा

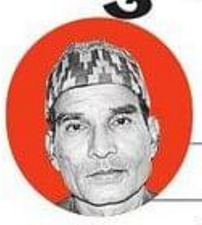

इस बार लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत ऐसी पहली घटना है।

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

अपराध

लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस समय पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। लेकिन पिछले 20 मार्च को पंजाब के संगरूर जिले में जहरीली शराब से पांच की मृत्यु हो गई और कुछ लोग भर्ती किए गए। मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 तक पहुंच गई। इस घटना का तत्काल ही चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव व डीजीपी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। इस बार लोकसभा चुनावों में आचार संहिता लागू होने के बाद जहरीली शराब पीने से मौत की यह पहली घटना है।

वर्ष 2019 में ओडिशा में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उस दौरान भी 30 अप्रैल, 2019 में भद्रक जिले में जहरीली शराब पीने से पांच लोग मरे व 28 बीमार हुए थे। उस दिन राज्य में चौथे व अंतिम चरण का मतदान था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, राजनीतिक पार्टियों द्वारा बांटे गए पैसे से लोगों ने शराब खरीदी थी और राजनीतिक दलों द्वारा भी शराब बांटी गई थी।

सितंबर, 2022 में हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनावों के दौरान जहरीली शराब कांड हुए थे। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मई, 2021 में अस्सी लोग मर गए थे।

लोकसभा, विधानसभा या पंचायतों के चुनावों में भी मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार कच्ची-पक्की, सस्ती-महंगी शराब बांटते रहते हैं। इसलिए चुनाव आयोग नकदी के साथ शराब या नशीले पदार्थों पर भी निगरानी रखता है। अभी देश भर में शराब पकड़ी जा रही है। राज्यों में इसके लिए विशेष छापामार दस्ते तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड में तो ड्रोनों की मदद से शराब बनाने वालों पर नजर रखी जा रही है।

संगरूर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का गृह जिला भी है। वह जब प्रभावित परिवारों से मिलने गए, तो गांव वालों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा खुलेआम चल रहा है। इस कांड की जांच के लिए विशेष उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन हो चुका है। दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

संगरूर कांड में नकली शराब में मिथेनॉल पाया गया। शराब बनाने के लिए ये रसायन मिथाइल अल्कोहल नोएडा से तथा बोतलें व ढक्कन बनाने का सामान लुधियाना से खरीदा गया था। बताया जा रहा है कि शराब बनाने की जानकारी यूट्यूब से जुटाई गई थी और कुछ जरूरी सामान ऑनलाइन भी खरीदा गया था। पंजाब पुलिस और आबकारी विभाग को छापों में जगह-जगह हजारों लीटर शराब, सैकड़ों खाली व भरी अवैध शराब की बोतलें, पेटियां एवं भट्ठियां मिल रही हैं। किंतु मौके पर शराब बनाते अपराधी कम ही पकड़े जा रहे हैं।

हालांकि सांविधानिक प्रतिबद्धता देश में मद्यपान को कम करने की है, किंतु राज्य ज्यादा से ज्यादा शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं। उनका तर्क होता है कि इससे अवैध व नकली शराब के जोखिम कम होंगे। अनुमानतः औसतन राज्यों को करीब ढाई लाख करोड़ का राजस्व शराब की बिक्री से मिलता है। इसलिए कोरोना महामारी के दौरान बंद शराब की दुकानों को खुलवाने के लिए राज्य बेताब थे। शराब बनाने, वितरण, प्रबंधन आदि राज्यों का विषय है। 19 जुलाई, 2022 को गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में संसद को बताया कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच जहरीली शराब पीने से देश में 6,000 मौतें हुई थीं।

देखने में आता है कि विभिन्न जहरीली शराब कांडों में जो अपराधी पकड़े जाते हैं, वे पहले भी ऐसे ही कारोबारों में कई बार सजा व जमानत पाए हुए होते हैं। बाहर निकलते ही वे फिर से पुराने धंधे में लग जाते हैं। संगरूर घटना के ज्यादातर आरोपी पहले ही हिस्ट्रीशीटर थे। संगरूर हादसा होली से ठीक पहले हुआ था, जब शराब की मांग बढ़ जाती है। शराब की मांग बढ़ जाने पर शराब तस्करों के साथ-साथ अन्य अपराधी भी नकली शराब के धंधे में सक्रिय हो जाते हैं।

जब भी ऐसी कोई घटना होती है, तो दोषियों को मौत की सजा देने की भी मांग उठने लगती है, फिर धीरे-धीरे सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। ऐसी घटनाओं पर खूब जमकर राजनीति होती है और भारी मुआवजे की मांग होती है। कई बार ऐसी घटनाओं में पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत की भी बात सामने आई है। जब तक अवैध शराब बनाने वालों और उन्हें सहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे दर्दनाक हादसे होते रहेंगे।

नए युद्ध की आशंका

अरब दुनिया में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इजरायल तो पहले से ही आक्रामकता की सीमाएं लांघता आ रहा है और अब उसके मुकाबले में ईरान ने भी उतनी ही आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर ली है। विशेषज्ञों की मानें, तो ईरान किसी भी वक्त इजरायल के किसी ठिकाने को निशाना बना सकता है। इधर इजरायल भी जवाब देने के लिए पूरी तरह चौकस मुद्रा में है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि एक दिन के अंदर ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्किये, चीन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री यह समझाने की कोशिश में लगे हैं कि मध्य-पूर्व में तनाव में वृद्धि किसी के हित में नहीं है। यहां यह कहना जरूरी है कि अमेरिका कमजोर दिख रहा है, उसका ईरान के साथ वर्षों से तनाव है और वह सीधे ईरान को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, तो वह उन देशों के नेताओं की मदद ले रहा है, जो ईरान पर खासा प्रभाव रखते हैं।

यहां अमेरिका को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर यह नौबत क्यों आई? इजरायल की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन उसकी बेलगाम आक्रामकता का बचाव कैसे किया जा सकता है? गाजा को तबाह करने के बावजूद इजरायल संघर्ष विराम के लिए तैयार नहीं है। फलस्तीन पर बम बरसाते छह महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी भले ही उसने न ली हो, पर ईरान के संदेह को दूर करने के लिए भी उसने कुछ खास नहीं किया है। ईरान 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के लिए इजरायल को लगातार दोषी ठहरा रहा है, जिसमें 'इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' के वरिष्ठ सदस्य मारे गए थे। ईरान पर दबाव है कि वह अपने लोगों की मौत का बदला ले और अगर ऐसा होता है, तो अरब दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा या युद्ध का विस्तार हो जाएगा। यह दुनिया के लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इजरायल भी गाजा के अलावा अन्य जगहों पर भी जंग के लिए तैयार है और उससे भी दुखद यह कि अमेरिका किसी भी सूरत में इजरायल की सुरक्षा से समझौता करने को तैयार नहीं होगा। यह भी चिंता बढ़ाने वाली बात है कि अमेरिका ने इजरायल में अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा है।

ईरान पर आंतरिक दबाव है कि वह अपने लोगों की मौत का बदला ले और अगर ऐसा होता है, तो अरब दुनिया में एक नया युद्ध छिड़ जाएगा या युद्ध का विस्तार हो जाएगा।

किसी नए मोर्चे पर अगर युद्ध भड़कता है, तो उसका व्यापक असर होगा। मिसाल के लिए, इजरायली सरकार ने घोषणा की है कि श्रमिकों की कमी से निपटने और देश के निर्माण उद्योग की सहायता के लिए 6,000 से अधिक भारतीय श्रमिक अप्रैल-मई के बीच इजरायल आएंगे। मतलब, युद्ध के भड़कने से भारतीयों की चिंता में भी इजाफा होगा। रूस-यूक्रेन युद्ध में भी भारतीयों को अनावश्यक रूप से तनाव का सामना करना पड़ा है। युद्ध और युद्ध क्षेत्र से भारत का न्यूनतम संबंध रहे, तो ही अच्छा। भारत अक्सर आक्रामक देशों को समझाता रहा है कि युद्ध किसी के हित में नहीं है, पर जाहिर है, दुनिया के अनेक देशों के लिए अमन-चैन के खास मायने नहीं हैं। जहां इजरायल की तारीफ संभव नहीं, वहीं ईरान की भी प्रशंसा नहीं हो सकती। हमास और हिज्बुल्लाह जैसे निर्मम-खूंखार आतंकी संगठनों के पक्ष में ईरान का होना बहुत दुखद और शर्मनाक है। सभ्य दुनिया में अपनी मांग रखने और उसके लिए संघर्ष करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, इसलिए सीधे आतंकवादियों की मदद की अमानवीय परिपाटी उन सभी देशों को छोड़नी पड़ेगी, जो दुनिया में वाकई अमन-चैन चाहते हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 13 अप्रैल, 1949

राष्ट्रमंडल और भारत

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों का प्रस्तावित सम्मेलन ज्यों-ज्यों निकट आ रहा है, राष्ट्रमंडल के साथ भारत के भावी सम्बन्ध का प्रश्न विशेष महत्व पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान का क्या रुख होगा, यह तो उसके एक राजदूत के इस कथन से भासित होता है कि पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से अलग नहीं होना चाहता। भारत में भी अधिकृत रूप से यह नहीं कहा गया है कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग ही रहेगा, किन्तु भारत का स्वतंत्र प्रजातंत्र होने का निश्चय सर्वविदित है। विधान परिषद् में यद्यपि अंतिम रूप से यह निश्चय अभी नहीं हुआ है, किन्तु इससे हटने का कोई विचार अभी तक सामने नहीं आया, बल्कि प्रधानमंत्री पं. नेहरू बार-बार उसकी पुष्टि ही करते आये हैं। प्रश्न यह है कि स्वतंत्र प्रजातंत्र बनकर भारत क्या राष्ट्रमंडल में रह सकता है?

परस्पर विरोधी विचार इस सम्बन्ध में सामने आये हैं। आयर का उदाहरण जहां हमारे सामने है, वहां ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक बहुत सधे हुए एवं माननीय राजनीतिज्ञ फील्ड मार्शल स्मट्स का यह स्पष्ट मन्तव्य हाल ही में सामने आया है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्र ब्रिटिश ताज की वफादारी के सम्बन्ध से बंधे हुए हैं, जो स्वतंत्र प्रजातंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता, स्वतंत्र प्रजातंत्र की दशा में राष्ट्रमंडल में नहीं रहा जा सकता और मैत्री ही संभव है, जैसी अन्य स्वतंत्र राज्यों के साथ रहती है। इसका मतलब हुआ कि भारत को राष्ट्रमंडल के साथ रहना है, तो वह अपने को स्वतंत्र प्रजातंत्र घोषित न करे और ब्रिटिश ताज की वफादारी को स्वीकार करे जो उसका उपनिवेश बनकर ही रहे। यह ऐसी स्थिति है जो भारत को स्पष्ट ही मान्य नहीं है। कारण, ताज की वफादारी का स्रोत इसमें है कि ब्रिटेन पितृदेश है, जहां के निवासियों ने आकर उपनिवेश बसाये और इसलिए उन्हें पितृदेश के प्रति कृतज्ञतापूर्ण वफादारी रखनी चाहिए। भारत पर यह बात लागू नहीं होती। भारत का सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ पिता-पुत्र का नहीं, शासक-शासित का रहा है, जिसमें वफादारी स्वेच्छा मूलक नहीं बलात् रही; अब जब भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति पा ली है, तो ब्रिटेन के रुख और अपनी परिस्थिति को देखते हुए वह उसके साथ मैत्री तो रख सकता है, किन्तु उसे अपना पितृदेश नहीं मान सकता।

पूरा देश चुनावमय है। विचारों की भरमार है। निष्पक्षता, चंदा और आयोग पर रह-रहकर बहस हो रही है। 25 अप्रैल, 1986 को लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस हुई थी और तब भी चुनावी तंत्र को लेकर नेताओं की जो शिकायतें थीं, उनमें से कई अब भी कायम हैं।

आमने-सामने

चुनाव तंत्र के भ्रष्ट होने से खतरे में लोकतंत्र

यहां स्कैन करें

एस जयपाल रेड्डी | वरिष्ठ नेता व तत्कालीन सांसद

आर्थिक दिशा में अनवरत रूप से ढांचागत गंभीर असफलता के बावजूद हमारे देश में प्रजातंत्र न केवल अपना अस्तित्व बनाए हुए है, बल्कि यहां की जमीन में गहरी जड़ें जमा चुका है, परंतु हमें इस तथ्य की जानकारी रखनी होगी कि भारतीय राजनीति की इस एकमात्र उपलब्धि को भी चुनाव संबंधी प्रक्रिया में दोष को बढ़ावा देकर खतरा पैदा किया जा रहा है। समूचा चुनाव तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है, जिसका हमारे लोकतंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। चुनाव सुधार अब कोई अकादमिक मुद्दा नहीं रह गया है, जिस पर लगातार कार्यवाही की जानी है। चुनाव आयोग ने इस वर्ष के अपने प्रतिवेदन में तीन प्रकार के बलों अर्थात धनबल, बाहुबल तथा प्रचार के बल (मीडिया) द्वारा पैदा किए गए खतरों की बात की थी। इस सूची में दो किस्म के बलों अर्थात शासकीय बल तथा तंत्र बल को भी जोड़ देना चाहिए। वास्तव में, इन पांचों के बल को संक्षेप में 'एम' कह सकते हैं। ऐसे इन पांच बुरे बलों पर रोक लगा दी जाती है, तो मेरे विचार में सुधार की कोई भी बात स्वयं चुनाव आयोग से ही शुरू की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग को इसके गठन, इसके तंत्र, इसके अधिकार क्षेत्र और इसकी स्वायत्तता की दृष्टि से सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। ...मेरे विचार में इसका प्रमुख एक व्यक्ति न होकर तीन व्यक्ति होने चाहिए और इस चुनाव आयोग का प्रबंध चलाने के लिए व्यक्तियों का चयन अकेली सरकार की इच्छा पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। मेरा विचार यह है कि वास्तव में इनकी नियुक्ति करने से पहले विपक्ष तथा देश के प्रधान न्यायाधीश और सरकार, सभी की राय पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग के पास स्वयं का एक स्वतंत्र तंत्र होना चाहिए, नहीं तो इसे पुनः राज्य सरकार के स्तर के तंत्र के माध्यम से कार्य करना पड़ेगा।

निर्वाचन आयोग को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, जहां वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि दस से अधिक मतदान केंद्रों पर कब्जा किया गया है, पुनः मतदान कराने का आदेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

...आचार संहिता का पालन के बजाय उल्लंघन अधिक किया जाता है, इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि आचार संहिता को कानूनी अधिकार दिए जाएं। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो वे बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध होंगे। ... हम जानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट क्या कुछ कर सकते हैं। अकेले बिहार राज्य में ही मैं आपका ध्यान एक अन्य मामले की ओर आकर्षित कर सकता हूं। विधानसभा चुनाव में पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर ही उसी चुनाव अधिकारी द्वारा कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार को जीत का प्रमाणपत्र दे दिया गया। मैं आशा करता हूं कि आप चुनाव अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में किए गए भारी पक्षपात को समझेंगे। ...

हमें पर्याप्त कानूनी प्राधिकार के साथ एक ऐसी आचार संहिता तैयार करनी चाहिए, जिससे यह देख सकें कि सरकार के इन प्रचार माध्यमों का संकीर्ण व घृणित पक्षपातपूर्ण प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग न किया जाए।

अब मैं कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने की अनुमति देने के बारे में हाल ही में किए गए संशोधन की चर्चा करूंगा। सरकार कंपनियों से उप-कर के रूप में चंदा प्राप्त कर सकती है। उस धन को एकत्र करके निर्धारित मानदंडों के अनुसार विभिन्न दलों में बांटा जा सकता है। यदि कंपनियों को विशेषाधिकार दिया जाता है, तो कंपनियां दलों के सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा दल की संरक्षक शक्ति के आधार पर चंदा देंगी। इसलिए यह संशोधन केवल उस भ्रष्टाचार को नियमित करने के लिए है, जो हमारे चुनाव तंत्र को खा रहा है।...

मेरे विचार से हमारे राजनीतिक दलों का ढांचा आंतरिक कार्यकरण के मामले में पर्याप्त रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए एक व्यापक विधान के माध्यम से राजनीतिक दलों के कार्यकरण को नियमित करने तथा राजनीतिक दलों की अनिवार्य लेखा परीक्षा शुरू करने की आवश्यकता है। ... महोदय, हल्के और सतही उम्मीदवारों से भी बचने की आवश्यकता है। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि जमानत राशि को कम से कम 10 गुना बढ़ा दिया जाए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

प्रजातंत्र नहीं, तो आप चुनकर कैसे आए

यहां स्कैन करें

ममता बनर्जी | वरिष्ठ नेता व तत्कालीन सांसद

महोदय, जो बिल सदन में लाया गया है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकती हूं। सदन में मैंने डी एन रेड्डी और जयपाल रेड्डी का भाषण सुना है। उन्होंने यह कहा है, यदि यह बिल लीगलाइज हो गया, तब देश में 'डेमोक्रेसी' आएगी, अभी तक ऐसा नहीं है। जब डेमोक्रेसी नहीं है, तो... जयपाल जी इधर कैसे आए? हम लोग जो इधर आए हैं, डेमोक्रेसी के चलते आए हैं। यदि आप सारे देश की स्थिति देखें, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम का राज है, कर्नाटक में हेगड़े जी का राज है, पंजाब में अकाली का राज है, वहां बरनाला जी हैं, असम में एजीपी का राज है और त्रिपुरा में नितेन चक्रवर्ती, सीपीएम का राज है। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी पूंजीवादी सीपीएम का राज है। फिर भी आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, क्लीन डेमोक्रेसी नहीं है, चुनाव के नियम ठीक नहीं हैं, तो भारतवर्ष में विपक्षी दल कैसे चुनकर आ रहे हैं?

मार्क्सवादियों का गणतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र है, इसको अगर देखना है, तो पश्चिम बंगाल में आकर देखिए। पश्चिम बंगाल में जो इलेक्टोरल रोल्स है, उनको पूरी तरह से बदलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाते हैं और मतदाता सूचियों के साथ गड़बड़ी की जाती है। वहां भारत के विधि मंत्री अशोक सेन का नाम मतदाता सूची में नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन का नाम मतदाता सूची में नहीं है। हजारों नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं और अगर कुछ दिन और ऐसे रहे, तो मार्क्सवादी सरकार को हटाना पड़ेगा, कॉमरेड का नाम भी आएगा और दूसरे किसी आदमी का नाम नहीं आएगा। यह कितनी शर्म की बात है कि विधि मंत्री का नाम मतदाता सूची में नहीं है? जो देश के लिए कानून बनाता है, उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया? यह कितनी शर्म की बात है और ये लोग सदन में हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं?

मेरा कहना यह भी है कि आप पहचान पत्र मतदाताओं को दीजिए। पश्चिम बंगाल में जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनमें छोटे-छोटे बच्चों का भी नाम है और किसी मार्क्सवादी के पिता अगर मर जाते हैं, तो उनका भी नाम मतदाता सूची में रहता है। जब चुनाव होता है, तो उनके नाम पर भी वोट पड़ जाता है। यह कैसे होता है? मतदाता सूची में फर्जी नाम भी होते हैं और उनके नाम से वोट समय से पड़ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि सब मतदाताओं को पहचान पत्र दिए जाएं। अगर ऐसा किया गया, तो स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। ...चुनाव से पहले ये लोग गांव में जाते हैं और रास्ते पर सड़क बनाने के लिए ईंटें गिराते हैं और गांव वालों को गेहूं देते हैं, चावल देते हैं और साड़ियां देते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोगों को वोट दीजिए, हम सब गरीबों के दोस्त हैं। केंद्र सरकार जो रुपये देती है, ...वे रुपये राज्य सरकार खर्च नहीं करती और चुनाव के समय खर्च किया जाता है। ...प्रशासन में भी मनमानी करके ये अपने लोगों को मतदान के काम में लगाते हैं। ... सीपीएम के कॉडर का सुपरवाइजर घर-घर में जाता है और कांग्रेस के वोट काट देता है।...

हमारी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं सीताराम केसरी। कोष वही संभालते हैं। ...मार्क्सवादी पार्टी में कोषाध्यक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि कोषाध्यक्ष होने से सबको मालूम हो जाएगा कि आपके पास कितने रुपये हैं और वे रुपये आपके पास कहां से आते हैं? इसीलिए आप लोग अपनी पार्टी में कोषाध्यक्ष नहीं रखते हैं। पहले आपकी पार्टी का दफ्तर मिट्टी के मकान में था, लेकिन अब आठ वर्ष पहले जब से आप सत्ता में आए हैं, उसके बाद से आपकी पार्टी के पास बहुत बड़ा भवन हो गया है। आज पांच मंजिली इमारत में आपकी पार्टी का दफ्तर है। ये रुपये आपके पास कहां से आए? ये सारे रुपये, करोड़ों रुपये, आपने सत्ता में आने के बाद पार्टी के लिए इकट्ठा किए। अगर आपकी पार्टी में कोषाध्यक्ष होगा, तो यह सारा सबको मालूम हो जाएगा, इसीलिए, आप लोग अपनी पार्टी में कोषाध्यक्ष नहीं रखते हैं।

पश्चिम बंगाल में बूथ कैप्चरिंग होती हैं, बोगस वोटिंग होती है। वहां पुलिस के पास न ढाल है, न तलवार है, न कोई हथियार है। बूथों पर पुलिस के लोगों को लाठी लेकर खड़ा कर दिया जाता है। इससे पुलिस के लोग कैसे बूथ कैप्चरिंग या बोगस वोटिंग को रोक सकते हैं? यह जो वहां चल रहा है, उसको रोका जाना चाहिए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

कश्मीर घाटी में बदली हुई फिजा और चुनावी मुकाबला

यहां स्कैन करें

अश्विनी कुमार | वरिष्ठ पत्रकार

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों संघ शासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की छह संसदीय सीटें यहां की राजनीतिक पार्टियों के लिए सेमीफाइनल बन गई हैं। करीब दस साल बाद इस वर्ष सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। बहरहाल, इन छह संसदीय सीटों में से दो सीटें- उधमपुर-डोडा-कठुआ और अनंतनाग-राजौरी सीट भाजपा के लिए 'हॉट सीट' बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह उधमपुर-डोडा-कठुआ संसदीय सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मत पड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह से उनका मुकाबला है। लाल सिंह भी यहां से पूर्व में दो बार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में उनका टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा था, मगर आजाद भाजपा प्रत्याशी डॉ जितेंद्र सिंह से बुरी तरह हार गए थे। इस बार यहां मुकाबला तिकोना है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने भी पूर्व मंत्री जी एम सरूरी को खड़ा कर दिया है। जितेंद्र सिंह इस दावे के साथ वोट मांग रहे हैं कि देश की यह पहली संसदीय सीट है, जहां सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जिनमें तीन मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार लाल सिंह अपनी गिरफ्तारी और सहानुभूति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वह वोटरों से यह भी कह रहे हैं कि भाजपा बाहरी कारोबारियों को यहां बसाकर आपकी जमीनों का मालिकाना हक उनको दे देगी।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की 2022 की रिपोर्ट के बाद जम्मू संभाग के दो सीमावर्ती जिलों, पुंछ और राजौरी को जम्मू संसदीय सीट से काटकर कश्मीर के अनंतनाग जिले से जोड़ दिया है और इसका नया नाम अनंतनाग-राजौरी-पुंछ संसदीय सीट रखा गया है। पीडीपी प्रमुख व सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मंत्री व गुज्जर धर्मगुरु मियां अल्ताफ, अपनी पार्टी के जफर मन्हास और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी यहां से मैदान में हैं। भाजपा ने अभी तक यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। चर्चा है कि गुलाम नबी आजाद भाजपा और अपनी पार्टी से वार्ता कर रहे हैं, ताकि उनका रास्ता निरापद हो जाए। ऐसे में, यह भी हॉट सीट बन गई है।

कोई शक नहीं है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा बता रही है कि घाटी में हिंसा घट गई है, पत्थरबाजी रुक गई है और विकास तेज हो गया है।

अनंतनाग-राजौरी-पुंछ सीट राष्ट्रपति शासन के दौरान गठित हुई है। यहां सबसे ज्यादा गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ी मतदाता हैं। अनंतनाग जिले में अधिकतर मतदाता कश्मीरी हैं। भाजपा ने यहां से इसलिए भी अधिक उम्मीदें बांधी हैं, क्योंकि केंद्र ने गुज्जर-बकरवाल को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। जम्मू-रियासी संसदीय सीट से दो बार से भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार मैदान में हैं। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला से है। श्रीनगर संसदीय सीट भी काफी दिलचस्प बनती नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि सेहत ठीक न रहने की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में, उमर अब्दुल्ला के मैदान में आने की अधिक संभावना है।

इस बार लद्दाख सीट पर भी कड़ी टक्कर होने जा रही है। यह सीट बनाए रखने के लिए भाजपा ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा बता रही है कि कश्मीर में हिंसा घट गई है, पत्थरबाजी रुक गई है और विकास तेज हो गया है। पहले कश्मीर में विकास रुक गया था और पिछड़ों को विकास या सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा था। बुनियादी रूप से शांति और विकास को गति मिलने का फायदा भाजपा को होता दिख रहा है।

दूसरी ओर, विपक्ष की दलील है कि आर्थिक विकास तो पूरे देश में हुआ है। सरकार या भाजपा ने कश्मीर में कुछ भी अलग से नहीं किया है। वहां जो आर्थिक विकास दिखता है, वह रक्षा या सुरक्षा कारणों से ज्यादा हुआ है। विपक्ष बार-बार मांग कर रहा है कि राज्य का दर्जा कब लौटाओगे? कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बता दिया है कि सरकार में आने पर वह राज्य का दर्जा लौटा जाएगा। भाजपा भी उचित समय पर राज्य का दर्जा देना चाहती है। कुल मिलाकर, कश्मीर में अच्छा सियासी माहौल बन रहा है और मतदान प्रतिशत बढ़ने भी तय है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

राजनीति से क्यों डरना

राजनीति को तुम्हें अपने मार्ग से डगमगाने की शक्ति न दो। यदि तुम उससे डरते हो, तो तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। तुम्हें राजनीति के अवरोध को पार करना ही है। यह तुम्हारी शक्ति, वचनबद्धता और एकाग्रता की परीक्षा है।

तुम राजनीति से बच नहीं सकते, लेकिन उसमें उलझे रहकर उसे अपने मन में बसाकर रखना या न रखना, तुम्हारे ऊपर है। ईसाई धर्म के बारह प्रवर्तकों के बीच में राजनीति थी। बुद्ध और उनके अनुयायी भी राजनीति से घिरे थे। कृष्ण तो सिर से पांव तक राजनीति में डूबे हुए थे और तुम कहते हो, तुम्हें राजनीति में नहीं पड़ना? जितना अधिक तुम राजनीति से दूर रहना चाहते हो, उतना ही अधिक उलझते जाते हो। जब तुम किसी भी संस्था में राजनीति देखते हो, तो यह तुम्हारे लिए केंद्रित होने, अपने भीतर जाने का एक अच्छा मौका है कि बिना हताश हुए, बिना सब कुछ छोड़े, बिना संस्था को दोष दिए और बिना लोगों से दूर भागे। यह तुम्हारी कार्य-कुशलता और अनासक्ति को उन्नत करता है।

राजनीति के कई लाभ हैं। यह लोगों की विविधता को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों तथा प्रवृत्तियों से तुम्हारा सामना कराती है। राजनीति संपर्क की तुम्हारी कुशलता और कार्य-क्षमता को बढ़ाती है। यह तुम्हारे भीतर केंद्रीयता और वैराग्य लाती है। राजनीति तुम्हें झकझोरकर ज्ञान में रहने के लिए सक्षम करती है। यह स्वीकार करने की तुम्हारी क्षमता और सहनशक्ति को बढ़ाती है। राजनीति तुम्हें यह अनुभव कराती है कि यह संपूर्ण जीवन एक खेल है। राजनीति की देहरी को पार करके ईश्वर की ओर आ जाओ। सबल व्यक्ति राजनीति से हंसते हुए निकल जाएंगे और कमजोर रोते रहेंगे!

श्री श्री रविशंकर

अमिताभ बच्चन | अभिनेता X

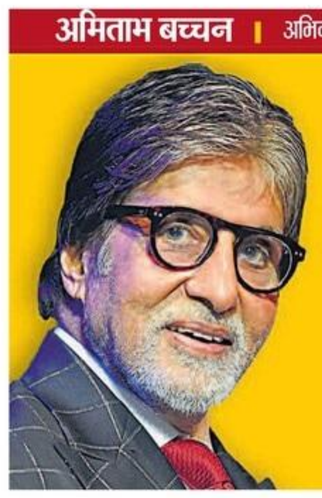

दुनिया की अहम घटनाओं का दस्तावेजीकरण करते हुए किसी दूरंदेश का यह वाक्य भी क्या खूब दर्ज हुआ कि कोई युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई शांति कभी बुरी नहीं होती!

पैदावार बढ़ाने में कारगर नैनो-उर्वरक

नैनो-उर्वरकों के प्रयोग से खेती में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इससे तकनीकी की उन्नति और पर्यावरणीय हितों के साथ-साथ व्यावसायिक परिवर्तन की भी पूरी संभावना है। मगर इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। नैनो-उर्वरकों के प्रयोग से उत्पन्न तकनीकी संभावनाओं के बारे में हमें गहनता से सोचना होगा। इससे हमें पौधों के पोषण और उत्पादन में सुधार का रास्ता मिल सकता है, लेकिन इसके प्रयोग के तरीके को और प्रभावी बनाने के ठोस प्रयास करने होंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग कृषि की समृद्धि और पर्यावरण के लिए हो, न कि केवल लाभ कमाने के लिए। व्यावसायिक परिवर्तन के साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि कैसे इसे सुगमता से किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न कदम उठाने होंगे, जिनमें उनकी जागरूकता और तकनीकी सहायता शामिल है। हमें सोचना होगा कि कैसे इस प्रक्रिया को समायोजित किया जा सकता है। नैनो-उर्वरक के प्रयोग के साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सके, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।

मौजूदा समय में नैनो-उर्वरकों का प्रयोग केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण के हित में भी होना चाहिए। इसके लिए हमें तमाम संभावनाओं का विस्तार से अध्ययन करना होगा और इसे कृषि के संरक्षण और समृद्धि के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास करना होगा। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करना होगा कि खेतों में उन्हें तकनीकी सहायता मिले। उन्हें इसके लाभ और उपयोग के बारे में शिक्षित करना होगा। जरूरत यह भी है कि सरकार इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करे, ताकि नैनो-उर्वरक जैसी पहल किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो। इसके लिए हमें उर्वरक का उत्पादन बढ़ाना होगा।

कई अध्ययनों ने इस बात की तस्दीक की है कि नैनो-उर्वरक पैदावार बढ़ाने में काफी कारगर हैं। ऐसे वक्त में, जब भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपने अतिरिक्त उत्पादन से कई देशों की खाद्यान्न जरूरतें पूरी कर रहा है, तब हमें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि हम अधिक से अधिक लोगों का पेट भर सकें। अच्छी बात है, सरकार इस दिशा में संजीदा है। उम्मीद है, आने वाले वक्त में नैनो-उर्वरकों से हम दुनिया पर मंडरा रहे खाद्यान्न संकट का हल निकाल सकेंगे।

अवनीश कुमार गुप्ता, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

नैनो यूरिया

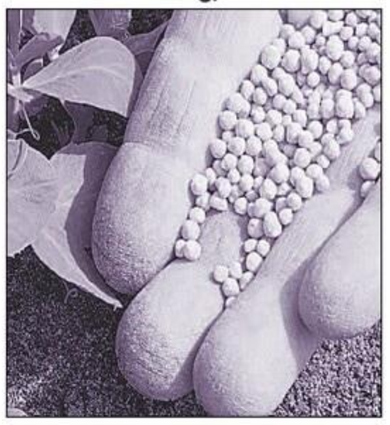

नई तकनीक पर्यावरण के अनुकूल भी हो

रासायनिक उर्वरकों से पर्यावरण पर पड़ते दुष्प्रभाव से शायद ही कोई अनजान होगा। यह हमारी मिट्टी के पोषक-तत्वों को तो खत्म करता ही है, खाद्यान्न की पोषकता को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, अनियंत्रित रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से जमीन बंजर होने लगती है और खाद्यान्न उत्पादन घटने लगता है। नैनो-उर्वरकों को भी अपवाद नहीं मानना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तब भी यही कहा गया था कि इससे हमारी खेती को खूब लाभ होगा। निस्संदेह, इसने हमारा उत्पादन बढ़ाया, लेकिन हमारे सामने कई चुनौतियां भी पेश कीं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ इसने इंसानों को भी कई बीमारियों की सौगात दी। आलम यह रहा कि पंजाब से चलने वाली एक ट्रेन को बाकायदा 'कैंसर एक्सप्रेस' कहा जाने लगा, क्योंकि उससे ज्यादातर कैंसर के मरीज ही यात्रा करते दिखाते हैं।

ठीक यही नैनो-उर्वरकों के साथ भी हो सकता है। भले अभी तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि नैनो-उर्वरक पौधों के भीतरी हिस्सों में जमा हो सकते हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित हो सकता है। इससे प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का निर्माण हो सकता है और पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है। कहा यह भी जाता है कि नैनो-उर्वरक खाद्यान्न में जमा हो सकता है और जब उनका सेवन किया जाएगा, तो मानव स्वास्थ्य के सामने कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

साफ है, नैनो-उर्वरक के इस्तेमाल को लेकर हमें सावधानी बरतनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी नई तकनीक को नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन जरूरी यह है कि उस पर भरोसा करने से पहले उनके अच्छे-बुरे गुणों का पर्याप्त अध्ययन होना चाहिए। इससे हम उस तकनीक का संभलकर इस्तेमाल कर सकेंगे और उसके दुष्प्रभावों के खिलाफ अपनी तैयारी रख सकेंगे। अगर नैनो-उर्वरक हमारी खेती को फायदा पहुंचाते हों, तो बेशक उसका किसान उपयोग करें, लेकिन यदि कहीं भी शक-ओ-सुबहा हो, तो कुछ क्षण ठहरकर हमें विचार करना ही चाहिए और फिर इसके इस्तेमाल की ओर बढ़ना चाहिए। जब अध्ययन नैनो-उर्वरकों के दुष्प्रभावों की भी पुष्टि कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें संभलकर आगे बढ़ना चाहिए? ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव का हमने खूब खामियाजा भुगता है। इस हमें सबक के तौर पर लेना चाहिए और नैनो-उर्वरकों की तरफ संभलकर कदम बढ़ाना चाहिए।

दीपक, टिप्पणीकार

कल्पमेधा

अपने विश्वासों में हमें जो कुछ मिला, वह ऐसा जीवन है, जिसमें विश्वास से ही बिखराव आता है। शंका से हमारा विश्वास इतना बिखर गया है।

– राबर्ट ब्राउनी

जासूसी का जिन्न

अब एक बार फिर जासूसी का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया लगता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने का दावा करने वाली कंपनी एप्पल ने अपने उत्पाद का उपयोग करने वालों को संदेश भेजा है कि उनके फोन में पेगासस जासूसी साफ्टवेयर के जरिए सेंधमारी की जा सकती है, इसलिए सावधान रहें। यह संदेश उसने मेल के जरिए भारत सहित इक्यानबे देशों के लोगों को भेजा है। करीब छह महीने पहले भी उसने भारत के कुछ लोगों को चेतावनी भेजी थी कि उनका फोन पेगासस के निशाने पर हो सकता है। उनमें ज्यादातर लोग विपक्षी दलों के नेता थे, इसलिए इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। मगर सरकार के दबाव में तब एप्पल ने अपनी उस चेतावनी को बहुत धुंधला कर दिया था। इस बार उसने बहुत गंभीरता और भरोसे के साथ अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि आपके फोन को 'मर्सीनरी स्पाईवेयर' के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उसने उन लोगों के नाम उजागर नहीं किए हैं, जिनके फोन में इस जासूसी साफ्टवेयर के जरिए सेंधमारी के तथ्य उसे हाथ लगे हैं। मगर कंपनी ने माना है कि इस तरह के हमले दुनिया भर हो रहे हैं।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एप्पल के अत्यंत सुरक्षित माने जाने वाले फोन में सेंधमारी की जा रही है, तो बाकी एंड्रायड से चलने वाले फोनों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। चूंकि एप्पल का सारा कारोबार इसी विश्वास पर टिका हुआ है कि उसके फोन और कंप्यूटर में कोई सेंधमारी नहीं कर सकता, उसके लिए भी यह बड़ी चुनौती बन चुका है। एप्पल ने माना है कि यह घुसपैठ किसी सामान्य साइबर सेंधमार के वश की बात नहीं है, क्योंकि जिस साफ्टवेयर के जरिए यह हमला किया जा रहा है, उस पर लाखों डालर का खर्च आता है और उसे लेना सबके बूते की बात नहीं। एप्पल इस साफ्टवेयर से पार पाने का कोई इंतजाम कर पाएगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, मगर दुनिया की तमाम सरकारें अब फिर से लोगों की निजता में सेंध लगाने को लेकर निशाने पर आ जाएंगी। करीब तीन साल पहले भारत में जब पेगासस के इस्तेमाल की बात सामने आई थी, तब खासा बवाल मचा था। सर्वोच्च न्यायालय में कई अपीलें दायर की गई थीं। यह साफ्टवेयर इजराइल की सरकार बेचती है और उसका कहना है कि वह इसे किसी स्वतंत्र व्यक्ति या कंपनी को नहीं बेचती, बल्कि सरकारों को देती है। इसलिए भी यह मामला ज्यादा गंभीर बन गया था।

साइबर सेंधमारी से लेकर डीपफेक आदि पहले ही भारत जैसे देश में एक गंभीर समस्या के रूप में सामने है, जिससे पार पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर पेगासस जैसे साफ्टवेयर के जरिए जासूसी और सेंधमारी का मामला सिद्ध होता है, तो यह ज्यादा गंभीर बात होगी। यह साफ्टवेयर दरअसल एक प्रकार का गुप्त भेदिया है, जो ग्राहक की नजरों से ओझल रह कर उसके फोन के जरिए उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। इस साफ्टवेयर को चुपके से किसी के भी फोन में डाला जा सकता है और फिर उस फोन के कैमरे, माइक वगैरह को अपने ढंग से संचालित किया जा सकता है। एप्पल के दावों को दरकिनार करना मुश्किल है। इस तरह सेंधमारी हो रही है, तो यह लोगों की निजता पर बड़ा आघात है। इस पर सरकार को गंभीरता से पहल करनी चाहिए।

नाहक जिद

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की विडंबना है कि जिस मुद्दे पर वे गंभीरता दर्शाना चाहते हैं, उसी में घिर जाते हैं। कनाडा के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अच्छी बात है, लेकिन अगर इस बहाने वे एक आतंकवादी की हत्या के लिए भारत को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो यह उनकी नाहक जिद ही कही जाएगी। गौरतलब है कि बुधवार को एक समिति के सामने गवाही में उन्होंने एक बार फिर खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया और परोक्ष रूप से भारत की ओर अंगुली उठाई। ट्रूडो ने इस मसले को हवा देते हुए कहा कि उनकी सरकार कनाडा के सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़ी है। अपने नागरिकों के हित और हक की रक्षा करना किसी भी देश की सरकार का दायित्व है। मगर क्या इस बहाने उसे किसी अन्य देश के खिलाफ काम करने वाले तत्त्वों का समर्थन करने का अधिकार भी मिल जाता है?

कनाडा के प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक तकाजों को ताक पर रख कर ऐसा करना चाहते हैं, तो यह उनका चुनाव हो सकता है। लेकिन उनके इस रुख का औचित्य इससे भी तय होगा कि क्या उनके बयानों से किसी अन्य देश की संप्रभुता पर आंच आती है! निज्जर की हत्या को अब दस महीने हो गए हैं। ट्रूडो ने इस घटना के लिए भारत पर अंगुली उठाई थी, जबकि भारत ने इससे साफ इनकार किया। विडंबना है कि अपने आरोप दोहराते हुए ट्रूडो अब तक मांगे जाने के बावजूद निज्जर की हत्या से संबंधित कोई भी ठोस सबूत देने में नाकाम रहे हैं। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि कनाडा के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर वे निज्जर हत्या में भारत का हाथ होने की बात कहते हैं तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या पड़ता है! आखिर निराधार आरोप की बुनियाद पर भारत को कठघरे में खड़ा करके उन्हें अपने देश में क्या हासिल हो जाएगा? उनकी इस नाहक जिद की वजह से भारत की छवि पर जो असर पड़ता है, उसकी भरपाई क्या वे कर पाएंगे?

कानों में कहर बरपाती आवाजें

वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का मानना है कि लगातार शोर में रहने के कारण व्यक्ति को भय मिश्रित बेचैनी होने लगती है; उसके रक्तचाप में गड़बड़ी हो जाती और दिल की सक्रियता पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

सिद्धायनी जैन

अक्सर प्रदूषण की बात करते हुए ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों की चर्चा नहीं होती। तेज आवाज सामान्यतया किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग अपने मौज-मजे के लिए तेज आवाज का 'आनंद' लेते और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई जलसों में ऐसा हुआ है कि तेज आवाज वाले संगीत पर नाच रहे लोग अचानक या तो गंभीर रूप से बीमार हो गए या उनकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का मानना है कि लगातार शोर में रहने के कारण व्यक्ति को भय मिश्रित बेचैनी होने लगती है; उसके रक्तचाप में गड़बड़ी हो जाती और दिल की सक्रियता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ये स्थितियां किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकती हैं। हो सकता है कि आनंद के अतिरेक में नाच रहे व्यक्ति को पता ही न चलता हो कि जिसे वह नृत्य के कारण पैदा हुई थकान समझ रहा है, वह दरअसल शोर के कारण उत्पन्न हुई स्थिति है, जो उसके शरीर के प्राणतत्त्व से खिलवाड़ करने लगी है। यह खतरा उन लोगों के लिए और बढ़ जाता है जो पहले से ही हृदय संबंधी किसी परेशानी, रक्तचाप की अस्थिरता या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं।

दरअसल, तेज आवाज खासकर शहरी जीवन की एक ऐसी बुराई बनती जा रही है, जिसका अभिशाप भुगतने के लिए हर नागरिक विवश है। सड़कों पर चारों ओर वाहनों की चिल्ल-पों होती है। चूंकि सबको कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, इसलिए जरा-सा जाम लगते ही वाहन चालक हार्न बजाने लगते हैं। बाहर के शोर से बचने के लिए लोग अक्सर अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ाकर सामान्य से अधिक आवाज में संगीत चला लेते हैं। रेलों, बसों में यात्रा करते या सड़कों पर चलते युवा अपने कानों पर हेडफोन लगाए होते हैं। कई बार इन हेडफोन की आवाज इतनी तेज होती है कि पीछे से आ रही कार का लगातार बजता हार्न भी नहीं सुनाई देता। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आवाज उसके कानों में जा रही होगी, उसकी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कितनी होगी? कई शोधों से पता चला है कि लोगों में लगातार बढ़ रहे चिड़चिड़ेपन और सड़कों पर वाहन चालकों में होने वाली झड़पों का कारण यह शोर ही है। हमारे आसपास बढ़ता शोर लगातार खतरे का कारण बन रहा है, लेकिन लोग हैं कि अपने आनंद को उन्माद में बदलने की जिद के आगे कुछ समझने को तैयार नहीं हैं।

मनुष्य के सुनने की क्षमता सीमित है। एक सामान्य मनुष्य को एक डेसीबल तीव्रता वाली आवाज आसानी से सुनाई दे जाती है। डेसीबल आवाज के स्तर को नापने की इकाई है। सामान्य तौर पर तीस डेसीबल से अधिक की आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यह स्तर जब 120 डेसीबल से अधिक हो जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो अजीब-सी बेचैनी होने लगती है। सुनने वाले का रक्तचाप बढ़ जाता है और इन स्थितियों का असर शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ने लगता है।

बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह स्थिति कई बार जानलेवा हो जाती है।

मनुष्य के सुनने की क्षमता सीमित है। एक सामान्य मनुष्य को एक डेसीबल तीव्रता वाली आवाज आसानी से सुनाई दे जाती है। डेसीबल आवाज के स्तर को नापने की इकाई है। सामान्य तौर पर तीस डेसीबल से अधिक की आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यह स्तर जब 120 डेसीबल से अधिक हो जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, तो अजीब-सी बेचैनी होने लगती है। सुनने वाले का रक्तचाप बढ़ जाता है और इन स्थितियों का असर शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ने लगता है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह स्थिति कई बार जानलेवा हो जाती है।

डीजे कई बार इस स्तर से भी ऊपर चले जाते हैं। सड़क किनारे बने मकानों के निवासी कई बार इस शोर के कारण अपने मकान के खिड़की-दरवाजों में कंपन महसूस करते हैं। इन दिनों चुनाव की गहमागहमी है। रैलियों और जुलूसों के दौर में इस तरह का शोर और बढ़ जाएगा। प्रचार के लिए किराए पर लिए गए वाहन लगातार गली-गली में ऊंची आवाज में प्रचार करते हुए निकलेंगे। ऐसे में, लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मिलने वाली चुनौतियों की चिंता कौन करेगा?

ध्वनि विस्तारकों के कारण होने वाले शोर के स्तर का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब कोई कुत्ता लगातार भौंकता है, तो 60 से 80 डेसीबल की आवाज उत्पन्न करता है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि कोई श्वान अगर लगातार भौंकता है तो एक अजीब किस्म की चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है। ऐसे में उनकी पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है, जिनके घरों के सामने कोई बरात या जुलूस रुकता है और डीजे पर ऊंची आवाज में बजने वाले गाने पर लोग देर तक नाचते रहते हैं।

कुछ न्यायालयों ने सड़कों पर डीजे के शोर के संबंध में निर्णय भी दिए हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों की पालना कराने वाली एजंसियां अपेक्षित कार्यवाही नहीं करतीं। इसका कारण यह भी है कि लोग ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आमतौर पर शिकायत नहीं करते और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना और उन्हें अदालत तक ले जाना पुलिस के लिए भी अपना कार्यभार बढ़ाने जैसा लगता है। करीब आठ वर्ष पहले प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मध्यप्रदेश के खरगौन में बकायदा डीजे वालों की मीटिंग लेकर उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पाबंद किया था कि किसी जुलूस, रैली, जलसे या यात्रा में 10 डेसीबल से अधिक आवाज पर डीजे नहीं चलेगा, अन्यथा दोषी को छह माह का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके करीब दो वर्ष बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए विवाह समारोह आयोजित करने वालों को डीजे बजाने से संबंधित एक निर्देशिका जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि डीजे निर्धारित मानक के स्तर तक ही चलाया जाए। पता नहीं इन सीखों की पालना कितनी हुई है।

दुनिया भर में शोर चिंता का सबब बनता जा रहा है। यह केवल प्रदूषण नहीं, बल्कि उपद्रव है, क्योंकि दूसरों की शांति को बाधित करता है। सन 2005 में स्पेन में एक सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें पाया गया कि लोग अच्छी-खासी रकम खर्च करके भी ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पाना चाहते हैं। अमेरिका में आवाजों के स्तर के लिए मानक बनाए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के नियम बनाने के लिए यहा प्रांतों की सरकारों और स्थानीय निकायों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। कनाडा और यूरोपीय संघ के देशों में भी ऐसे कानून हैं, जो ध्वनि प्रदूषण से आम आदमी की रक्षा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 85 डेसीबल से अधिक की आवाज को शोर मानते हुए बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर कई बार चिंता प्रकट की है।

किसी शायर ने लिखा है कि 'ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।' मगर ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यह शोर, जो हमारे आसपास पसरता जा रहा है, सचमुच हमें शांति से जीने नहीं देगा।

खुशी की तलाश में

नरेंद्र सिंह 'नीहार'

धर्मशास्त्रों में मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को माना गया है, पर एक सामान्य मनुष्य से पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए तो उसका सीधा और सपाट उत्तर होगा- खुशी। इसी कड़ी में अगला सवाल हो सकता है कि आपको कितनी खुशी चाहिए! इसके बाद शायद वह दोनों हाथ खोलकर और आसमान की ओर देखकर कह देगा- जीवनपर्यंत। हर साल हर दिन। यानी चौबीसों घंटे और सातों दिन। यों यह पूछने वाली कोई बात तो है नहीं! सभी मनुष्य खुश ही रहना चाहते हैं। यह मनुष्य की मूल चाहत है। इस संदर्भ में इतिहास में एक शानदार उद्धरण मिलता है। मकदूनिया का शासक सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह अपने अभियान पर निकलने से पहले एक फकीर डायोजनीज से आशीर्वाद लेने गया। डायोजनीज समुद्र किनारे रेत पर धूप का आनंद ले रहा था। सिकंदर ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दुनिया को जीतकर विश्व विजेता बन सकूं। इस पर डायोजनीज ने पूछा कि उससे क्या होगा! सिकंदर ने जवाब दिया- 'मुझे खुशी मिलेगी'। यह सुन कर डायोजनीज ने उसे झिड़कते हुए संकेत दिया- 'मेरे ऊपर आ रही धूप छोड़ दो, क्योंकि मेरी खुशी बाधित हो रही है।' सिकंदर उसका मंतव्य जाने और समझे बिना वहां से चला गया।

इस दृष्टांत से एक बात स्पष्ट है कि हमारी खुशी हमारे पास नहीं है। वह किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या सफलता रूपी चिड़िया के पास अलग-अलग रूप में रखी हुई है। हम खुश होने के लिए जी रहे हैं या फिर खुशी के साथ जी रहे हैं। दोनों मनोभावों में अंतर है। जब हम खुशी के साथ जीते हैं तो उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं। बड़े से बड़ा काम भी बोझ नहीं लगता है और जब हम खुश होने के लिए जीते हैं तो कई बार ऊब और थकान महसूस करते हैं। दबाव और तनाव हमारे ऊपर अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। यह हमारे मनोबल को कमजोर कर देता है और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसके विपरीत जब हम खुश रहकर सकारात्मक सोच के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है।

खुशी एक आंतरिक मनोभाव है, जिसे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि अपने व्यक्तित्व और सोच-समझ के मुताबिक हम अपनी खुशी की पहचान कर लें। सामान से सम्मान के रास्ते पर चलने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। बड़ा घर और कोई बड़ी गाड़ी पाकर उनकी प्रसिद्धि और प्रसन्नता में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। मगर यह मिलने तक ऐसे लोग अतृप्त और व्याकुल ही बने रहते हैं। सामान की तरह का सुख क्षणिक होता है। हमें खुशी चाहिए तो जीवन से अभावों को निकाल दिया जाए। आधिक्य के भाव में जीने का अभ्यास खुशी का संचार करता है। व्यक्ति की व्याकुल मानसिकता पर विराम लग जाएगा। डायोजनीज के पास कुछ नहीं था, फिर भी वे प्रकृति के सान्निध्य में खुश थे और सिकंदर राजा होकर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अकिंचन बना हुआ था। बड़े से बड़ा पद, प्रतिष्ठा और अकूत दौलत भी किसी को खुशी की गारंटी नहीं दे सकते हैं।

निरंतर शिकायतों और अभावों में जीना हमारे जीवन की रंगत छीन लेता है। हम दुखिया होकर जग भर को अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं। हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, उसमें हमसे सहानुभूति जताने या हमारी समस्याओं को दूर करने के बजाय ज्यादार लोग पीठ पीछे मजाक भी बनाते होंगे। दरअसल, यह एक सांस्कृतिक समस्या है कि जन्म से लेकर बड़े होने तक सबको जैसा माहौल मिलता है, लोग उसी में रमते चले जाते हैं। जिन हालात पर सोचने-समझने का जैसा स्वरूप तय किया गया होता है, वैसे ही सोचने की परंपरा जारी रहती है। बहुत कम लोग होते हैं, जो एक तयशुदा ढांचे से अलग होकर सोचते हैं और नई परिस्थितियां रचते हैं। ऐसे लोगों को अगर अपनी समस्या के बारे में बताया जाए तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक हो सकती है। वे हमें अभाव से निकलने का कोई रास्ता बता सकते हैं। मगर आमतौर पर अभाव की वजह से पीड़ित लोगों से सब बचना ही चाहते हैं।

इसलिए इस भाव से जीने का अभ्यास करना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है! हाथ-पांव, दिल-दिमाग, बुद्धि-चातुर्य, शिक्षा-नौकरी और परिवार सब कुछ तो है। स्वयं को व्यवस्थित करना है। कुदरत का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हम अपनी आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा से आसपास के वातावरण को तरोताजा बना सकते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि बड़े से बड़े धनवान लोग भी अपने जीवन के लिए सुख की तलाश में सुकून प्राप्त करने वाले ठिकानों को ही ढूंढ़ते हैं। जो लोग इस समाज में अवसर का लाभ उठाने वाले लोगों की प्रवृत्ति को समझते हैं, वे इस तरह के लोगों को अपने रास्ते में बाधक मानते हैं। अपने ऐश्वर्य से चमकते जीवन के बरक्स वे अपने आसपास के प्रतिस्पर्धी और चापलूसी भरे माहौल से बाहर निकल कर कभी सामान्य व्यक्ति की तरह भी कुछ पलों को जीना चाहते हैं। खुली हवा में सांस भरना चाहते हैं। इस दिशा में प्रकृति का सान्निध्य और उसका कल-कल निनाद सुनना भी सेहत के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। वास्तविक खुशी समझदारी और जीवन को दृष्टा भाव से जीने में ही मिलेगी।

दुनिया मेरे आगे

सामान से सम्मान के रास्ते पर चलने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। बड़ा घर और कोई बड़ी गाड़ी पाकर उनकी प्रसिद्धि और प्रसन्नता में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। मगर यह मिलने तक ऐसे लोग अतृप्त और व्याकुल ही बने रहते हैं। सामान की तरह का सुख क्षणिक होता है। हमें खुशी चाहिए तो जीवन से अभावों को निकाल दिया जाए।

मिलावट के कारोबारी

आमतौर पर मिलावटखोर अपना भ्रष्ट कारोबार हर वक्त चलाते रहते हैं, लेकिन कुछ पर्व-त्योहारों पर वे कुछ अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा विवाह आदि के मौसम में ये मिलावटखोर अधिक फलते-फूलते हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इनकी तरफ से आंख मूंदकर बैठे रहते हैं। इसका कारण जगजाहिर है। ऐसा नहीं कि केवल खाद्य पदार्थों में ही ये मौत का खेल खेला जाता है, बल्कि जीवन रक्षक दवाइयों में भी मौत के ये व्यापारी मिलावट करने से नहीं चूकते। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से जहरीली शराब से मरने के समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं। मगर विभाग कार्रवाई के नाम पर कुछेक ठिकानों पर छापा मारकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। इन चोरों पर आर्थिक दंड लगाकर अधिकारी फिर शांति से बैठ जाते हैं। जबकि किसी मिलावट वाले खाद्य पदार्थ से किसी की जान जा सकती है। ऐसे तमाम होटल जहां ऊंची कीमत लेकर मिलावटी मावा, पनीर, दूध यहां तक कि पानी भी ग्राहकों को परोसा जा रहा है। अगर इन पर हत्या की धाराएं लगाकर अभियोग चलाया जाए, तो शायद तभी वे इस कुकृत्य को करने से पूर्व सौ बार सोचेंगे।

– नरेंद्र टोंक, मेरठ

वक्त रहते

'जल है तो कल है' (दुनिया मेरे आगे, 11 अप्रैल) पढ़ा। वास्तव में अगर एक प्यासे व्यक्ति से अमृत और जल के बीच विकल्प चुनने को कहा जाए तो वह जल को चुनेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें हिमालय के रूप में स्वच्छ पेयजल का अक्षय स्रोत और तीन ओर से विशाल समुद्र का भंडार मिला है जो मानसूनी वर्षा में सहायक है। मगर हम अंधाधुंध विकास और नगरीकरण की दौड़ में अपनी इस समृद्ध प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहे हैं। हम पानी को अनुदान समझकर उसके प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझते। गोमुख बहुत तेजी से पीछे की ओर जा रहा है और ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब पूरे दक्षिण एशिया की प्यास बुझाने वाली नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इस ग्रह को निर्जन बनाते जा रहे हैं। हमें तत्काल भूजल के उपयोग पर सीमाएं लगानी होंगी और वर्षा जल संग्रहण और जल संभार प्रबंधन को अनिवार्य बनाना होगा।

– ज्योत प्रकाश गुलाटी, रोहतक

चमकती छवि

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिससे भारत का मान वैश्विक स्तर पर बहुत बढ़ गया है। 'अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड' के साथ-साथ भारत को संयुक्त राष्ट्र में कई महत्त्वपूर्ण निकायों का दायित्व भी मिला है, जो बेहद महत्त्वपूर्ण है। भारत की जगजीत पवाडिया ने तीसरी बार 'अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड' में निर्वाचित होकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर मार्च 2025 से 2030 तक अपना कार्यकाल सुनिश्चित किया है। साथ ही 2025 से 2027 की परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण, विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कार्यकारी बोर्ड में भी भारत को चुना गया है। यह निश्चित ही भारत के लिए गर्व की बात है।

– पारस जैन, मेरठ

अनदेखी का हासिल

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का पद से इस्तीफा दिल्ली के अनुसूचित जाति/ जनजाति समुदाय की भावना के अनुरूप दिखाई पड़ता है। दिल्ली सरकार पर मंत्री ने अनुसूचित जाति वर्ग की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है और हवाला देते हुए कहा था कि तेरह राज्यसभा के सांसदों में से एक भी अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को मंत्री के इस्तीफे के बाद संभल जाना चाहिए कि दिल्ली के बड़ी तादाद में रह रहे दलित समुदाय की अनदेखी इस लोकसभा चुनाव में कहीं भारी न पड़ जाए। इसलिए अविलंब इन मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

www.readwhere.com